लखनऊ

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

शुक्रवार 9 जनवरी, 2026

वर्ष : 11 । अंक: 140

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

एक दिन, तुम जागोगे और पाओगे कि उन चीज़ो को करने के लिए समय नहीं बचा है जो तुम हमेशा करना चाहते थे, इसलिए जो भी करना है अभी कर लो।

TODAY WEATHER

DAY 20° Hi

NIGHT 10° Low

उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने एनसीसी कैडेट्स से की मुलाकात, कहा- ऑपरेशन सिंदूर से बढ़ा भारत का गौरव

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोमवार को कहा कि सशस्त्र बलों की तरीफ की। उन्होंने कहा कि पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सशस्त्र बलों ने भारत को गौरवान्वित किया। उन्होंने सैन्य कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए दुनिया को देश के दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। दिल्ली छावनी में राष्ट्रीय कैडेट कोर के गणतंत्र दिवस शिविर 2026 में अपने संबोधन में उन्होंने ऑपरेशन के दौरान एनसीसी के प्रशंसनीय योगदान की भी सराहना की।

उन्होंने कहा, 'ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एनसीसी ने सराहनीय योगदान दिया, जब लगभग 72,000 एनसीसी कैडेट नागरिक सुरक्षा उपायों के लिए स्वेच्छा से सेवाएं देकर एनसीसी योद्धा बन गए।' अधिकारियों के अनुसार, इन कैडेटों ने आपातकालीन अभ्यास, रक्तदान शिविरों और अन्य नागरिक सुरक्षा संबंधी गतिविधियों में सहायता की। 7 मई, 2025 की सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में कम से कम 100 आतंकवादियों को मार गिराया गया। पहलगाम हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की मौत हो गई थी।

भारत को ऐसे युवाओं की जरूरत, जो साहसी होने के साथ दयालु भी हो

उन्होंने कहा, 'आज के तेजी से बदलते वैश्विक परिवेश में, भारत को ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो साहसी होने के साथ-साथ दयालु भी हों, तकनीकी रूप से कुशल होने के साथ-साथ अच्छे मूल्यों में दृढ़ हों, चुनौतियों का सामना दृढ़ता से करें और अवसरों को आत्मविश्वास के साथ भुनाएं। उन्होंने एनसीसी कैडेटों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करने की उनकी एकता और अनुशासन की भावना नागरिकों के बीच बहुत आशा और आत्मविश्वास जगाती है। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कोर की प्रशंसा की और कहा कि एनसीसी एक बार फिर युवा विकास और राष्ट्र की प्रगति के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है।

ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक शक्तिशाली प्रतीक- उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन

उपराष्ट्रपति ने कहा, 'पिछले साल, हमारी सशस्त्र सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम देकर दुनिया को भारत के दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया, जिससे देश को गौरवान्वित किया।' आगे उन्होंने कहा, 'ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सशस्त्र बलों की राष्ट्र के सम्मान, संप्रभुता और उसके नागरिकों की रक्षा करने की अटूट प्रतिबद्धता का एक शक्तिशाली प्रतीक था।' इसके साथ ही उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने सोमवार को एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया, जिसका समापन 28 जनवरी को प्रधानमंत्री की रैली के साथ होगा। देश भर से कुल 2,406 एनसीसी कैडेट, जिनमें 898 लड़कियां शामिल हैं, लगभग एक महीने तक चलने वाले इस शिविर में भाग ले रहे हैं। अपने संबोधन में उन्होंने कैडेटों को केवल गणतंत्र दिवस शिविर में भाग लेने वाले नहीं, बल्कि एक नए भारत के राजदूत के रूप में वर्णित किया, जो 2047 तक एक 'आत्मनिर्भर' और मजबूत भारत, एक विकसित भारत के निर्माण में योगदान देंगे। उपराष्ट्रपति ने कहा, 'आप में से प्रत्येक में, मुझे एक विकसित भारत की मजबूत नींव दिखाई देती है, एक विकसित, समावेशी और आत्मविश्वासी देश की नींव दिखाई देती है।' उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक विकसित राष्ट्र के निर्माण की दिशा में एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू हो गई है। इसके केंद्र में आत्मनिर्भरता है, जो कुशल, अनुशासित और मूल्यों से प्रेरित युवाओं द्वारा संचालित आत्मनिर्भरता की भावना है, राधाकृष्णन ने कहा।

संक्षेप

डिप्टी चेयरमैन के अधिकारों पर जस्टिस वर्मा ने उठाए सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जो नियुक्ति करता है वो रद्द भी

नई दिल्ली। कैश कांड मामले पर सुनवाई में गुरुवार (8 जनवरी, 2026) को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जज की नियुक्ति को मंजूरी दे सकते हैं तो वह नियुक्ति को रद्द भी कर सकते हैं। कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की उस दलील पर यह बात कही है, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्यसाभा के चेयरमैन की अनुपस्थिति में डिप्टी चेयरमैन के अधिकार सीमित हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राज्यसभा के नए चेयरमैन चुने जाने तक जांच कमेटी बनाया जाना रोका जा सकता था। उन्होंने लोकसभा की तरफ से जांच कमेटी बनाने का यह कह कर विरोध किया है कि प्रस्ताव दोनों सदनों में पेश हुआ था, लेकिन राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर ने उसको खारिज कर दिया तो सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष कैसे जांच कमेटी बना सकते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव 21 जुलाई को लाया गया था और उसी दिन राज्यसभा के चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद 11 अगस्त को डिप्टी चेयरमैन ने प्रस्ताव खारिज कर दिया और 12 अगस्त को लोकसभा अध्यक्ष ने जांच कमेटी बनाने की मंजूरी दे दी। बुधवार को भी इस मामले में सुनवाई हुई थी और जस्टिस यशवंत वर्मा की दलीलों पर जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने पूछा था कि राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन की तरफ से प्रस्ताव खारिज करने के बाद लोकसभा स्पीकर की तरफ से कमेटी बनाने में गलत क्या है।

500% टैरिफ लगेगा, चीन पर नरम भारत पर गरम, करना क्या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे बिल को मंजूरी दे दी है, जिससे रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। इसके बाद भारत और चीन पर अमेरिकी टैरिफ बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, कुछ मामलों में यह 500 फीसदी तक पहुंच सकता है। यह कदम यूक्रेन युद्ध के बीच रूस पर दबाव बनाने के लिए उठाया गया है। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने सोशल मीडिया पर बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बिल को आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के साथ बैठक अच्छी रही और इस बिल पर अगले हफ्ते संसद में वोटिंग हो सकती है। यह बिल लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेट सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने मिलकर पेश किया है। इसके तहत ऐसे देशों पर सख्ती की जा सकेगी जो जानबूझकर रूस से तेल और यूरेनियम खरीद रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि इससे रूस को जंग जारी रखने के लिए पैसा मिलता है। सीनेटर ग्राहम के मुताबिक, इस बिल से राष्ट्रपति ट्रंप को भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर दबाव बनाने की ताकत मिलेगी, ताकि वे सस्ता रूसी तेल खरीदना बंद करें। पिछले साल ट्रंप ने भारत से आने वाले सामान पर 25 फीसदी टैक्स लगाया था। इसके साथ ही रूस से तेल खरीदने पर 25 फीसदी का अतिरिक्त टैक्स भी लगाया गया। इससे कुछ भारतीय सामानों पर कुल टैक्स 50 फीसदी तक पहुंच गया और दोनों देशों के रिश्तों में खटास आई।

'ऑपरेशन सिंदूर ने जागरूक किया, राष्ट्र निर्माण में योगदान जरूरी'

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा है कि 'ऑपरेशन सिंदूर' ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि जीवन सिर्फ पैसा कमाने या निजी उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण में योगदान देना भी उतना ही जरूरी है। दिल्ली कैंट में आयोजित राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) गणतंत्र दिवस शिविर को संबोधित करते हुए वायुसेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एनसीसी कैडेट्स की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस सैन्य कार्रवाई के समय नागरिक सुरक्षा, आपात अभ्यास और रक्तदान शिविरों में कैडेट्स का योगदान समाज के लिए प्रेरणादायक रहा। एयर चीफ मार्शल सिंह ने कैडेट्स से कहा कि चाहे वे भविष्य में सशस्त्र बलों में शामिल हों या किसी अन्य क्षेत्र को चुनें, उन्हें हमेशा देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। उन्होंने असफलताओं से निराश न होने की सलाह देते हुए अपने जीवन का उदाहरण साझा किया और कहा कि उन्होंने भी कई उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन अंततः वायुसेना प्रमुख बनने का अवसर मिला, जो उनके मुताबिक नियति में लिखा था। वायुसेना प्रमुख ने कहा, 'चाहे आप वर्दी में सैनिक हों या आम नागरिक, देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देना और राष्ट्र निर्माण में योगदान करना हर किसी का कर्तव्य है।' वायुसेना प्रमुख ने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने लोगों में यह जागरूकता बढ़ाई कि जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए कुछ करना भी है। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 की सुबह भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर चलाया गया था।

बेटे अग्निवेश के निधन पर वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने शेयर किया भावुक पोस्ट, पीएम मोदी ने जताया दुख

नई दिल्ली, एजेंसी। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का अमेरिका में निधन हो गया। वह 49 साल के थे। सोशल मीडिया पर अनिल अग्रवाल के एक्स पोस्ट को शेयर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा दुख व्यक्त किया और श्रद्धांजलि दी है। प्रधानंत्री मोदी ने लिखा, श्री अग्निवेश अग्रवाल का असामयिक निधन अत्यंत दुखद और स्तब्ध करने वाला है। इस भावपूर्ण श्रद्धांजलि में आपके गहरे शोक की झलक स्पष्ट है। प्रार्थना है कि आपको और आपके परिवार को शक्ति और साहस मिलता रहे। ओम शांति। इससे पहले उद्योगपति अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, आज मेरे जीवन का सबसे दर्दनाक दिन है। मेरा

अग्निवेश, मेरा 49 साल का बेटा, आज हमारे बीच नहीं रहा। एक बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी जाए इससे बुरा और क्या हो सकता है। अग्निवेश अपने दोस्त के साथ अमेरिका में स्कीइंग करने गया था। वहां एक्सीडेंट हो गया। वो माउंट सिनाई हॉस्पिटल, न्यूयॉर्क में ठीक हो रहा था। हमें लगा सब ठीक हो जाएगा... लेकिन अचानक कार्डियक अरेस्ट हो गया। और हमारा बच्चा हमें छोड़कर चला गया। उद्योगपति अनिल अग्रवाल ने आगे लिखा कि 3 जून 1976 को पटना में जब अग्नि हमारी दुनिया में आया, वो पल आज भी आंखों के सामने है। एक मिडिल क्लास बिहारी परिवार में जन्मा था अग्नि। तुम्हारे साथ बिताया गया हर एक पल आज बहुत याद आ रहा है बेटा। अपनी मां का दुलारा अग्नि बचपन में बेहद चंचल और शरारती था। हमेशा हंसता, हमेशा मुस्कुराता। यारों का यार था वो और अपनी बहन प्रिया को लेकर सबसे प्रोटेक्टिव भी। उसने मेयो कॉलेज, अजमेर में पढ़ाई की। बेहद स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी अग्नि की-बॉक्सिंग चैंपियन, हॉर्स राइडिंग का शौकीन और कमाल का म्यूजिशियन। उसने फुजैराह गोल्ड जैसी शानदार कंपनी खड़ी की और हिंदुस्तान जिंक का चेयरमैन भी बना, लेकिन इन सबसे ऊपर अग्नि बेहद सिंपल था। हमेशा अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के बीच में ही रहता था। जिससे भी मिलता, उसे अपना बना लेता था। वो हमेशा जमीन से जुड़ा रहा-सीधा, सच्चा, जिंदादिली और इंसानियत से भरा। वो सिर्फ बेटा नहीं था- वो मेरा दोस्त था, मेरी शान था, मेरी पूरी दुनिया था। अग्रवाल ने आगे लिखा, मैं और किरन टूट से गए हैं। बस यही सोच रहे हैं कि हमारा बेटा तो चला गया लेकिन जो लोग हमारे वेदांता में काम करते हैं, वो सब अग्निवेश ही तो हैं। वो सब हमारे बेटे-बेटियां हैं। अग्नि और मेरा सपना था हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाना। वो हमेशा कहता था- पापा, हमारे देश में क्या नहीं है? फिर हम किसी से पीछे क्यों रहें? हमारी दिली इच्छा यही रही कि देश का कोई बच्चा भूखा न सोए। कोई बच्चा अनपढ़ न रहे। हर महिला अपने पैरों पर खड़ी हो और सभी युवाओं को रोजगार मिले। उन्होंने लिखा कि मैंने अग्निवेश से वादा किया था हमारे पास जितना भी धन आएगा, उसका 75 प्रतिशत से ज्यादा समाज के काम में लगाएंगे।

जज साहब! कुत्ते हटे तो चूहे बढ़ जाएंगे... सुप्रीम टिप्पणी- बिल्लियां पाल लो

नई दिल्ली, एजेंसी। आवारा कुत्तों के केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज गुरुवार को भी हुई। कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए अन्य जानवरों के जीवन पर भी सवाल उठाए हैं। कुत्ता प्रेमियों की तरफ से केस लड़ने वाले वकील सीयू सिंह ने कोर्ट में कुत्तों का पक्ष रखते हुए कहा- जज साहब... अगर गलियों से आवारा कुत्तों को हटाया गया, तो चूहों की तादाद अचानक से बढ़ सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट तल्ख टिप्पणी करते हुए दो टूक शब्दों में कहा- तो क्या बिल्लियां ले आएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कुत्ते और बिल्लियां स्वाभाविक दुश्मन हैं और बिल्लियां चूहों को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- क्या इसका कुत्तों को हटाने से कोई लेना-देना था। हल्के-फुल्के अंदाज में

कहें तो, कुत्ते और बिल्लियां दुश्मन हैं। बिल्लियां चूहों को मारती हैं, इसलिए हमें ज्यादा बिल्लियों और कम कुत्तों को बढ़ावा देना चाहिए। यही समाधान होगा। हमें बताएं कि आप हॉस्पिटल के गलियारों में कितने कुत्ते घूमते हुए देखना चाहते हैं। वकील सीयू सिंह ने कहा- भारी संख्या में आवारा कुत्तों को एक ही शेल्टर में रखने से कई बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। ऐसे में कुत्तों के लिए 91,800 नए शेल्टर बनाए जाने चाहिए।

सीनियर एडवोकेट ध्रुव मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए कहा- आखिरी बार कुत्तों की मॉनिटरिंग 2009 में हुई थी। तब दिल्ली में सिर्फ 5,60,000 कुत्ते थे। मगर, अब इनकी संख्या बढ़ चुकी है। इसलिए कुत्तों की मॉनिटरिंग करना बेहद जरूरी है। कोर्ट में एक अन्य याचिकाकर्ता की तरफ से दलील देते हुए सीनियर एडवोकेट नकुल दीवान ने कहा- मेरे क्लाइंट एक एनजीओ चलाते हैं, जिसमें 45 लोग काम करते हैं। उनकी टीम ने अब तक 66000 से ज्यादा कुत्तों की जान बचाई है और 15000 कुत्तों की नसबंदी करवाई है।

खनन नीति में हुए बदलाव की कांग्रेस ने की आलोचना, जयराम रमेश बोले- ये मोदी सरकार का नया झटका

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस ने गैर-कोयला खनन परियोजनाओं से संबंधित पर्यावरण मंजूरी नियमों में बदलाव को लेकर सरकार की आलोचन की है। पर्यावरण मंत्रालय के हालिया ज्ञापन के अनुसार, गैर-कोयला खनन परियोजना विकासकर्ताओं को पर्यावरण मंजूरी के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब तक, मंत्रालय को भूमि अधिग्रहण का प्रमाण चाहिए होता था। कांग्रेस ने कहा कि यह जिम्मेदार पर्यावरण प्रशासन के लिए मोदी सरकार द्वारा एक और झटका है। कांग्रेस महासचिव और पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने कहा, गैर-कोयला खनन परियोजनाओं के लिए नीति यह रही है कि पहले कानून के अनुसार भूमि अधिग्रहण पूरा किया जाए।

इंदौर दूषित पानी मामले की न्यायिक जांच हो : दिग्विजय सिंह

भोपाल, एजेंसी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने इंदौर में दूषित जल पीने से हुई मौत और सैकड़ों लोगों के बीमार पड़ने के मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की। दिग्विजय सिंह ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर कहा है कि इंदौर मेरे बचपन का शहर, मेरे राज्य का सबसे विकसित शहर और देश का सबसे स्वच्छ शहर है। राज्य की आर्थिक राजधानी में इसकी गिनती होती है, और उसी इंदौर शहर में 18 लोग गंदा पानी पीने से मर जाते हैं। जब तक आंकड़ा 2-4 मौत का रहा, किसी ने सांस नहीं ली, लेकिन जब मौतों की गिनती बढ़ने लगी, तो सबने जिम्मेदारी की टोपी सब दूसरे को पहनाना शुरू कर दिया। मंत्री ने अफसर को, अफसर ने

मेयर को, मेयर ने व्यवस्था को और इन सब के बीच बात घंटे की लड़ाई पर उलझ गई। इंदौर के प्रभारी मंत्री पर सवाल उठाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री से कोई सवाल नहीं पूछ रहा कि वे हर दूसरे दिन शहर में आते हैं और वे महज मौत का मुआवजा देकर चुप क्यों हो गए? कुछ ट्रांसफर और मुआवजे से शहर का कलंक नहीं धुलता। पूर्व मुख्यमंत्री ने मांग की है कि इस हादसे की न्यायिक जांच हो, पब्लिक के सामने सुनवाई हो और हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच करायी जाए। उन्होंने आगे कहा कि मौत के मुआवजे से जिंदगी नहीं लौटती। गलतियों पर पर्दा डालने की बजाय गलतियों की जिम्मेदारी तय हो और उन्हें दंडित किया जाए। बता दें कि इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी की आपूर्ति से कई मौतें हुई हैं, वहीं सैकड़ों लोग बीमार हुए हैं। उसके बाद से राज्य के अन्य हिस्सों में भी दूषित पानी की आपूर्ति का मामला तूल पकड़ रहा है। इस मामले पर राजनीति भी खूब हो रही है। सरकार दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिला रही है।

महिला सुरक्षा में सबसे सुरक्षित शहर बेंगलुरु, दूसरे नंबर पर चेन्नई, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

नई दिल्ली, एजेंसी। देश में महिला सुरक्षा के मामले में बेंगलुरु और चेन्नई सबसे बेहतर शहरों के रूप में सामने आए हैं। वर्क प्लेस कल्चर कंसल्टिंग फर्म अवतार ग्रुप की रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है।

'टॉप सिटीज फॉर वीमेन इन इंडिया (TCWI) के चौथे संस्करण में यह बात सामने आई है कि इस रिपोर्ट में 125 शहरों की महिलाओं की भागीदारी रही। इन महिलाओं से सुरक्षा और करियर ग्रोथ के बारे में जानकारी ली गई। इसी आधार पर बेंगलुरु ने 53.29 के स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया है।

TCWI की रिपोर्ट एक लॉन्गिट्यूडिनल इन्क्लूजन इंडेक्स है, जो यह यह पता लगाने का काम

करती है कि किस शहर में महिलाओं की भागीदारी, सुरक्षा और करियर ग्रोथ को बेहतर बनाया जा रहा है।

बेंगलुरु बना नंबर 1 शहर

बेंगलुरु 53.29 CIS के साथ इस लिस्ट में टॉप पर है। बेंगलुरु के टॉप पर रहने की वजह यह भी है कि यहां महिलाओं के लिए करियर में ग्रोथ के लिए बेहतर अवसर हैं। साथ ही इंडस्ट्री सपोर्ट भी मिलता है। बेंगलुरु साल 2024 में भी इस लिस्ट में नंबर 1 बना था। वहीं साल 2025 में भी इस शहर ने महिलाओं की सुरक्षा में नंबर 1 का मुकाम हासिल किया है।

टॉप 10 में शामिल शहर

महिलाओं की सबसे ज्यादा सुरक्षा देने के मामले में दूसरे नंबर पर चेन्नई का नाम है। ये शहर 2024 में भी दूसरे नंबर पर आया था। इस लिस्ट में तीसरे पर पुणे और चौथे नंबर पर हैदराबाद है। मुंबई ने साल 2024 में इस लिस्ट में तीसरा नंबर हासिल किया था। लेकिन 2025 में मुंबई पांचवें नंबर पर आया है।

बेंगलुरु
चेन्नई
पुणे
हैदराबाद
मुंबई
गुरुग्राम
कोलकाता
अहमदाबाद
त्रिवेंद्रम
कोयंबटूर

सड़क दुर्घटना में मृत भिखारी के कंटेनर से मिला 45 लाख रुपये नकदी, विदेशी मुद्रा का था भंडार, अब किसे मिलेगा ये पैसा?

नई दिल्ली, एजेंसी। केरल के अलाप्पुझा में सड़क दुर्घटना में एक भिखारी की मौत हो गई। इसके बाद जब भिखारी के सामानों की जांच की गई तब एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ और भिखारी के कंटेनर को खोलकर देखा गया तो मौजूद अधिकारी भी दंग रह गए।

दरअसल, अलाप्पुझा के चारुम्मूट और आसपास के इलाके में एक भिखारी काफी समय से भीख मांगने का काम कर रहा था। सोमवार रात भिखारी सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद भिखारी बिना किसी को बताए अस्पताल से चला गया और अस्पताल के रिकॉर्ड के अनुसार, उस व्यक्ति ने अपना नाम अनिल किशोर बताया। हालांकि, मंगलवार सुबह एक दुकान के बाहर वो मृत पाया गया, जिसके बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उसके शव के पास से एक कंटेनर बरामद हुआ था, जिसे स्थानीय पंचायत सदस्य फिलिप उम्मान की उपस्थिति में खोला गया तो उसमें से 45 लाख रुपये से अधिक की नकदी बरामद हुई। इस नकदी में प्रतिबंधित 2000 रुपये के नोटों के साथ-साथ विदेशी मुद्रा भी शामिल था।

पुलिस ने बताया कि नकदी प्लास्टिक के डिब्बों में रखी गई थी। स्थानीय लोगों के अनुसार, किशोर प्रतिदिन भीख मांगता था और खाने-पीने के खर्च के लिए पैसे मांगता था। किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि वह इतनी बड़ी रकम अपने साथ ले जा रहा है।

भाजपा नेता पंकज चौधरी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा- मनरेगा में सुधार भ्रष्टाचार के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक

आर्यावर्त संवाददाता

वाराणसी। वाराणसी दौरे पर आए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जानबूझकर भ्रम फैला रही है। एसआईआर पूरी तरह से चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, लेकिन भाजपा एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते इसे लेकर धरातल पर जागरूकता फैला रही है।

पंकज चौधरी ने कहा कि जो मतदाता सूची सामने आई है, उसकी भाजपा कार्यकर्ता स्वयं जांच कर रहे हैं। वोट कटने की शिकायतें गंभीर

और चिंता का विषय हैं, इसलिए हर स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस संवैधानिक प्रक्रिया को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रही है।

इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मनरेगा योजना पर चर्चा करते हुए कहा कि वर्ष 2006 से लागू मनरेगा में कई खामियां थीं। अस्थायी सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा था, गड्ढे खोदकर भरने जैसे काम हो रहे थे और आर्थिक-सामाजिक लाभ नहीं मिल पा रहा था। नकली जॉब कार्ड बनाए जा रहे थे और जांच की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी।

उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश को कई बार सुधार के लिए पत्र लिखे गए, लेकिन यूपीए सरकार ने जानबूझकर आंखें मूंदे रखीं। मौजूदा सरकार ने मनरेगा में सुधार कर इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक बनाया है।

मनरेगा को लेकर कही ये बात

पंकज चौधरी ने कहा कि अब मनरेगा के तहत जल संरक्षण जैसे स्थायी कार्य कराए जाएंगे। योजना को पीएम गति शक्ति मिशन से जोड़ा गया है। अधिनियम में बदलाव कर राज्यों को 60 दिन तक कार्य रोकने का अधिकार दिया गया है। साथ ही मजदूरी भुगतान को लेकर सख्त निर्देश हैं। 15 दिन में भुगतान नहीं होने पर ब्याज देना होगा। उन्होंने दावा किया कि यूपीए सरकार के मुकाबले मौजूदा सरकार ने मनरेगा पर चार गुना अधिक खर्च किया है, जिससे गांवों के विकास को नई दिशा मिलेगी। सपा द्वारा जारी किए गए पीडीए कैलेंडर पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सपा खुद तय करे कि पीडीए का मतलब क्या है, क्योंकि वे आए दिन उसका अर्थ बदलते रहते हैं। अंत में उन्होंने दोहराया कि भाजपा सर्वसमाज की पार्टी है और बिना भेदभाव के काम कर रही है।

सपा विधायक व कद्दावर नेता विजय सिंह गोंड का निधन, लखनऊ में लंबे समय से चल रहा था इलाज

आर्यावर्त संवाददाता

सोनभद्र। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और दुद्धी विधायक विजय सिंह गोंड का लखनऊ के एसजीपीजीआई में इलाज के दौरान निधन हो गया। उनके निधन की पुष्टि विधानसभा अध्यक्ष अवधनारायण यादव ने की। लंबे समय से बीमार चल रहे विजय सिंह गोंड की दोनों किडनी खराब हो गई थी, जिसके चलते उन्हें एसजीपीजीआई में भर्ती कराया गया था।

आदिवासी समाज की आवाज बुलंद करने वाले अग्रणी नेताओं में शुमार थे

प्रदेश की 403वीं अंतिम विधान सभा सीट दुद्धी के आदिवासी राजनीति के 'पितामह' कहे जाने वाले गोंड के निधन से पूरे सोनभद्र और आस-पास के क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ गई। विजय सिंह गोंड आदिवासी

समाज की आवाज बुलंद करने वाले अग्रणी नेताओं में शुमार थे।

क्रांग्रेस के टिकट पर पहली बार विधानसभा चुनाव में मिली थी जीत

दुद्धी और ओबरा विधानसभा को अनुसूचित जनजाति सीट घोषित कराने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। वनवासी सेवा आश्रम में मात्र 200 रुपये मासिक मानदेय पर कार्यरत रहते हुए उन्होंने 1979 में कांग्रेस के टिकट पर पहली बार विधानसभा चुनाव जीता। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

आठ बार रहे विधानसभा के सदस्य

1989 में अपने राजनीतिक गुरु रामप्यारे पनिका को हराकर उन्होंने आदिवासी राजनीति में नया अध्याय लिख दिया। विभिन्न दलों से होते हुए वे आठ बार विधानसभा के सदस्य रहे और प्रदेश की राजनीति में आदिवासी हितों को नई पहचान दिलाई। गोंड ने सदन में आदिवासी समाज के अधिकारों को मजबूती से उठाया और उन्हें मुख्यधारा में लाने का उल्लेखनीय प्रयास किया। विजय सिंह गोंड के निधन से राजनीतिक, सामाजिक और आदिवासी समुदाय में गहरा शोक व्याप्त है। नेता, कार्यकर्ता और समर्थक उनके निधन को अपूरणीय क्षति मान रहे हैं।

राहुल नगर का प्रतीक्षालय बना 'शोभा की वस्तु'

आर्यावर्त संवाददाता

अखंडनगर/सुलतानपुर। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रियों की सुविधा के लिए लाखों-करोड़ों की लागत से बनाए जाने वाले प्रतीक्षालय रख-रखाव और गलत योजना के कारण दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला अखंड नगर ब्लॉक के राहुल नगर बाजार का है, जहाँ नवनिर्मित प्रतीक्षालय अपनी बदहाली पर आँसू बहा रहा है।

हैरानी की बात यह है कि इस प्रतीक्षालय का निर्माण अभी हाल ही में हुआ था, लेकिन पहली बारिश और कुछ ही समय के उपयोग में इसकी फर्श टूटने लगी है। घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल की आशंका जताते हुए स्थानीय निवासियों ने इसके स्थायित्व पर सवाल उठाए हैं।

प्रतीक्षालय की दीवारों पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें लगाई गई थीं। विडंबना यह है कि प्रशासन और संबंधित विभाग की लापरवाही के चलते ये तस्वीरें भी क्षतिग्रस्त (फटी हुई) अवस्था में हैं, जो सरकारी उदासीनता की पराकाष्ठा को दर्शाती हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह प्रतीक्षालय जनता के लिए 'सफेद हाथी' साबित हो रहा है। इसका मुख्य कारण इसका बाजार से बाहर होना है। ग्रामीणों का तर्कः यदि यह प्रतीक्षालय राहुल नगर बाजार के मुख्य केंद्र में बना होता, तो बस या सवारी का इंतजार करने वाले सैकड़ों यात्रियों को इसका लाभ मिलता। वर्तमान स्थितिः बाजार से दूर होने के कारण यात्री यहाँ रुकना पसंद नहीं करते, जिससे यह स्थान अब केवल लावारिस पशुओं या असामाजिक तत्वों का अड्डा बनने की ओर अग्रसर है। जब योजना जनता की सुविधा के लिए है, तो उसे जनता की पहुँच से दूर क्यों बनाया गया? यह सीधे तौर पर सरकारी धन की बर्बादी है।

कोहरे में भीषण हादसा : बरेली में ट्रक ने ई-रिक्शा को कुचला, दो लोगों की मौत... दो की हालत नाजुक

आर्यावर्त संवाददाता

रिठौरा (बरेली)। बरेली में बृहस्पतिवार सुबह कोहरे के कारण रिठौरा में राजश्री पेट्रोल पंप के नजदीक भीषण सड़क हादसा हो गया। हाईवे पर ट्रक ने ई-रिक्शा को रौंद दिया। पूरा ई-रिक्शा ट्रक के नीचे आने से कुचल गया। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। दो घायल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद ट्रक छोड़कर चालक भाग गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया है।

जानकारी के मुताबिक नवाबगंज क्षेत्र के यासीननगर निवासी हाशिम अपना ई-रिक्शा लेकर भोजीपुरा क्षेत्र के गांव लाडपुर में काम करने जा रहे थे। ई-रिक्शा में रिछोला निवासी सलीम, नसरुद्दीन और रहीसद्दीन उर्फ मंझले भी सवार थे। ये सभी लोग बोरिंग का काम करते थे। राजश्री

पेट्रोल पंप के नजदीक ट्रक चालक यू-टर्न ले रहा था। इसी बीच ट्रक ने सामने से आ रहे ई-रिक्शा को चपेट में ले लिया।

हादसे के बाद ट्रक छोड़कर भागा चालक

बताया गया कि चालक ने ट्रक नहीं रोका, जिससे ई-रिक्शा ट्रक के नीचे आ गया। हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर भाग गया। चीख-पुकार मचने पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही रिठौरा चौकी पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जेसीबी से ट्रक हटवाया। इसके बाद ई-रिक्शा में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। हादसे में ई-रिक्शा चालक हाशिम और सलीम की मौके पर ही मौत हो गई। नसरुद्दीन और रहीसद्दीन गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन्हें अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दी। परिजन रोते-बिलखते हुए मौके पर पहुंचे। शवों को देखकर उनका कलेजा कांप गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि जहां पर हादसा हुआ है, वहां सड़क का निर्माण हो रहा है। सुबह के वक्त कोहरा भी घना था। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है।

तुर्कमान गेट मस्जिद केस : अतिक्रमण के नाम पर ज्यादती, एसटी हसन बोले- मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी ने पार की हदें

आर्यावर्त संवाददाता

मुरादाबाद। दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास एमसीडी की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई को लेकर मुरादाबाद के पूर्व सांसद व सपा नेता एसटी हसन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह करीब 100 साल पुरानी मस्जिद है। अतिक्रमण के नाम पर जबरदस्ती की जा रही है।

ऐसे में लोग कब तक चुप रहेंगे। अगर यही कार्रवाई हर जगह समान रूप से होती तो लोग धैर्य रखते। लेकिन जब धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई होती है तो लोगों की भावनाएं जुड़ी होने के कारण उसका विरोध स्वाभाविक है। हसन ने कहा कि मस्जिदों, मदरसों और धार्मिक ढांचों को इस तरह कब तक गिराया जाता रहेगा। सवाल उठाया कि अगर कल दिल्ली की जामा मस्जिद को गिराने का फैसला कर लिया जाए तो क्या होगा। उसके स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज और स्वीकृत नक्शे भी मौजूद नहीं हैं, तब उसे भी अवैध माना जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमानों के प्रति दुश्मनी में सभी सीमाएं पार की जा चुकी हैं।

सपा नेता ने कहा कि यदि कहीं अवैध अतिक्रमण है तो कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए जिनकी मौजूदगी में यह सब हुआ। साथ ही उन्होंने हिंसा भड़काने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की मांग की है।

खेलों के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ने का मिल रहा मौका : पूर्व मंत्री

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लंभुआ/सुल्तानपुर। खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दे रही है। इस योजना का उद्देश्य पूरे देश में खेलों में युवाओं को प्रोत्साहित करना है। उक्त बातें भाजपा नेता व केपी सिंह पीजी कॉलेज के प्रबंधक हनुमान प्रसाद सिंह के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित दंगल प्रतियोगिता के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद पूर्व जल शक्ति मंत्री व वर्तमान एमएलसी महेंद्र प्रताप सिंह ने कही।

लंभुआ क्षेत्र में स्थित केपी सिंह पीजी कॉलेज मथुरा नगर रामगढ़ के प्राचार्य अवनीश कुमार उर्फ गुड्डू सिंह के नेतृत्व में संस्था प्रबंधक हनुमान प्रसाद सिंह के जन्मदिन के अवसर पर विशाल दंगल प्रतियोगिता के आयोजन में देश-विदेश के पहलवानों ने अपना दम खम दिखाया। दंगल प्रतियोगिता में दिल्ली,

जम्मू, राजस्थान, बिहार, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, जौनपुर, अयोध्या, गोंडा, कानपुर, सुल्तानपुर, मेरठ, प्रतापगढ़, गाज़ीपुर आदि जनपदों से काफी संख्या में पहलवान शामिल होने के लिए आए। इसके अलावा नेपाल से भी रूबी थापा ने भी अपना दमखम दिखाया। कई जनपदों से महिला पहलवान भी प्रतियोगिता में शामिल हुई। मुख्य अतिथि ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले पहलवानों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया। देर शाम तक प्रतियोगिता का आयोजन चलता रहा। मुख्य अतिथि श्री सिंह ने कहा कि ऐसे आयोजनों से क्षेत्र के युवाओं में उत्साह बढ़ता है और उन्हें भी खेल के माध्यम से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। प्रतियोगिता में आए हुए अतिथियों का आयोजक प्राचार्य अवनीश कुमार सिंह ने आभार व्यक्त किया। मौके पर डॉ. एके सिंह, एमएलसी प्रतिनिधि डिंपल सिंह, धनंजय सिंह, मनीष सिंह, विपिन सिंह, वेद प्रकाश सिंह,मल्ले सिंह, अखिलेश सिंह, प्रदीप सिंह, अवनीश सिंह राजीपुर, राहुल मिश्रा, प्रशांत चतुर्वेदी, हरिओम अग्रहरि, लल्लन सिंह, राकेश श्रीवास्तव आदि गणमान्य मौजूद थे।

बल्दीराय तहसील के 57 राजस्व गांव सदर तहसील में किए गए शामिल

सुलतानपुर। आखिरकार एक लंबे अंतराल के बाद बल्दीराय तहसील के 57 राजस्व गांव को सुल्तानपुर तहसील में शामिल किए जाने का आज आदेश जारी कर दिया गया। शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी कुमार हर्ष ने आज तत्काल प्रभाव से इस अधिसूचना का अनुपालन करने का निर्देश दे दिया है। गौरतलब हो कि इन 57 राजस्व गांव के लोगों के लिए सदर तहसील पास पड़ती थी, बावजूद इसके इन गांव को बल्दीराय तहसील बनाए जाने पर उनमें शामिल कर दिया गया था। लंबे समय से ग्रामीण इसकी मांग कर रहे थे, पूर्व में कई विधायकों और सांसदों से इसकी मांग भी की गई थी। कई बार लोगों ने चुनाव में मतदान बहिष्कार करने का अल्टीमेटम भी दिया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान विनोद सिंह ने इन राजस्व गांव के लोगों से वायदा किया था कि अगर वे चुनाव जीतते हैं तो हर हाल में इन गांव को सदर तहसील में जुड़वाया जाएगा।

अब्दुल हमीद एसोसिएशन ने गरीबों को बांटे कंबल

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। शहीद वीर अब्दुल हमीद एसोसिएशन, सुल्तानपुर द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम एक सराहनीय सामाजिक पहल का परिचायक है। ठंड के मौसम में जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम आज दोपहर 1 बजे शहीद वीर अब्दुल हमीद अस्पताल, नगर पालिका सुल्तानपुर परिसर में आयोजित हुआ।

इस मानवीय कार्यक्रम में चिकित्सा, समाजसेवा, राजनीति और संगठन से जुड़े कई सम्मानित नाम शामिल रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. ए.के. सिंह की उपस्थिति सराहनीय रही। डाक्टर ए के सिंह जो एक वरिष्ठ एवं अनुभवी चिकित्सक हैं और लंबे समय से समाजसेवा से जुड़े हुए हैं। उनके साथ डॉ. सुधाकर सिंह और डॉ. एस.पी. सिंह, सपा नेता शकील अहमद खान, व्यापारी नेता रविंद्रत्रिपाठी, संस्था के संरक्षक अब्दुल हई, जलील अंसारी, अब्दुल गफ्फार, संस्था मीडिया प्रभारी सुजीत कसौधन, मोहम्मद साकिब सरफराज अहमद, इरफान अहमद, गुड्डू जायसवाल,की गरिमामयी उपस्थिति सराहनीय रही। जो चिकित्सा के साथ-साथ सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभाते आ रहे हैं।

कार्यक्रम को सफल बनाने में शहीद वीर अब्दुल हमीद एसोसिएशन के अध्यक्ष मकरूल अहमद नूरी इदरीसी की अहम भूमिका रही, जिनके नेतृत्व में यह संस्था लगातार गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों की सेवा कर रही है। आयोजन में शहर के कई समाजसेवी, जनप्रतिनिधि, नेता, पत्रकार और संस्था के सक्रिय कार्यकर्ता भी शामिल रहे। जो इस नेक पहल को मजबूती प्रदान कर रहे थे।कंबल वितरण जैसे कार्यक्रम न केवल ठंड से बचाव का साधन बनते हैं, बल्कि समाज में भाईचारा, सहयोग और मानवता की भावना को भी मजबूत करते हैं। जब डॉक्टर, समाजसेवी, नेता और संस्था के कार्यकर्ता एक मंच पर आकर सेवा करते हैं, तो उसका प्रभाव कहीं अधिक व्यापक होता है। यह आयोजन देश के महान सपूत शहीद वीर अब्दुल हमीद को सच्ची श्रद्धांजलि है, जिनका जीवन राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित रहा। यह कार्यक्रम समाज को यह संदेश देता है कि सामूहिक प्रयासों से ही जरूरतमंदों के जीवन में राहत और मुस्कान लाई जा सकती है।

यूट्यूबर और यूपी पुलिस के दरोगा ने कार में नाबालिग से दरिंदगी!... तेल चोरी का खिलाड़ी है शिवबरन यादव

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

कानपुर। कानपुर के सचेंडी में 14 वर्षीय किशोरी को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने आरोपी यू-ट्यूबर शिवबरन यादव को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे आरोपी उपनिरीक्षक अमित मौर्य की तलाश जारी है। सोमवार रात हुई दरिंदगी की वारदात में इस्तेमाल की गई दरोगा की स्कॉर्पियो बरामद हो गई है।

एडीसीपी पश्चिम कपिल देव सिंह के सामने पीड़िता ने यू-ट्यूबर और दरोगा को आरोपी बताया, जिस पर पॉक्सो और सामूहिक दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाई गई। मामले में पुलिस कमिश्नर ने थाना प्रभारी विक्रम सिंह को निलंबित कर दिया, वहीं डीसीपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी को डीसीपी हेडक्वार्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

बुधवार सुबह एडीसीपी पश्चिम

कपिल देव सिंह पीड़िता के गांव पहुंचे। ग्रामीणों से जानकारी जुटाई तो लोगों ने सचेंडी थाने में तैनात रहे दरोगा अमित मौर्य की काले रंग की स्कॉर्पियो कार के बारे में जानकारी दी। एडीसीपी ने कार और आरोपियों की फोटो पीड़िता को दिखाई, जिसे उसने पहचान लिया। पीड़िता ने यू-ट्यूबर और दरोगा पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। इसके बाद सचेंडी पुलिस ने आरोपी यू-ट्यूबर शिवबरन को गिरफ्तार कर लिया। बृहस्पतिवार को पीड़िता के मजिस्ट्रेटी बयान लिए जाएंगे। सचेंडी के एक गांव निवासी युवक की ओर से दर्ज कराई रिपोर्ट के मुताबिक, उसकी 14 वर्षीय बहन सोमवार रात करीब 10 बजे किसी कार्य से घर से थोड़ी दूरी पर गई थी। काफी देर तक न लौटने पर घरवालों ने तलाश शुरू की। रात करीब 12 बजे वह वापस बदहवास हालत में लौटी। बताया कि रास्ते में काली कार सवार दो युवकों ने उसको अंदर खींच लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने अज्ञात कार सवारों पर दुष्कर्म और अपहरण की धाराओं में एफआईआर दर्ज की।

प्राथमिकी में पॉक्सो व सामूहिक दुष्कर्म की बढ़ाई गई धाराएं

दरोगा अमित मौर्य को निलंबित कर उसकी तलाश में चार टीमें लगाई गई हैं। डीसीपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। उन्हें डीसीपी हेडक्वार्टर की जिम्मेदारी दी गई है। तथ्यों से छेड़छाड़ करने, सही धाराओं में एफआईआर दर्ज न करने और अधिकारियों से जानकारी छिपाने में सचेंडी इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। एफआईआर में पॉक्सो और सामूहिक दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाई गई हैं।

– रघुबीर लाल, पुलिस कमिश्नर

दरोगा का बिठूर थाने में हुआ स्थानांतरण, नहीं कराई रवानगी

कानपुर में दुष्कर्म की वारदात में सहयोगी रहे आरोपी दरोगा अमित मौर्या का तीन दिन पहले ही बिठूर थाने में स्थानांतरण हो गया था लेकिन उसने रवानगी नहीं कराई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, दरोगा और यू-ट्यूबर के बीच साठगांठ करने की कई शिकायतें मिली हैं। उन पर तेल चोरी के खेल में शामिल होने का आरोप है।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सचेंडी में ऑयल लाइन से तेल चोरी करने का खेल लंबे समय से चल रहा है। इस कार्य में जुड़े आरोपियों को कुछ पुलिसकर्मियों और ट्यूबरों से सहयोग मिल रहा है। सूत्रों के मुताबिक, शनिवार की रात को आरपीएफ के एक इंस्पेक्टर ने आरोपी शिवबरन यादव को किसी अन्य आरोपी की जानकारी दी थी जिस पर वह दरोगा के साथ सचेंडी क्षेत्र में निकला था।

पीड़िता के भाई को गिरफ्तारी से पहले आरोपी ने धमकाया

सचेंडी में किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार शिवबरन पर पीड़िता के भाई ने धमकाने का आरोप लगाया है। बताया कि मंगलवार सुबह करीब 11 बजे गांव के बाहर खरीदारी करने गए थे। तभी आरोपी बाइक से आया पुलिस के सामने नाम बताने को लेकर देख लेने की धमकी दी। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना पर परिवार ने राहत की सांस ली है। परिवार ने आरोपी दरोगा की भी जल्द गिरफ्तारी की मांग की। वहीं, पुलिस ने पीड़िता के भाई का मोबाइल भी जब्त कर लिया। पीड़ित ने शिकायत की तो एडीसीपी पश्चिम कपिल देव सिंह ने पुलिसकर्मियों को फटकार लगाते हुए उसका फोन वापस दिलवाया।

यू-ट्यूबर तेल चोरी का खिलाड़ी, कई मामले दर्ज

गिरफ्तार किया गया यू-ट्यूबर शिवबरन सिंह यादव तेल चोरी का बड़ा खिलाड़ी है। उसके खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। पनकी पुलिस ने शिवबरन को उसके साथी नीरज के साथ सितंबर 2024 में तमंचे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सचेंडी पुलिस ने भी शिवबरन को काफी मात्रा में लीटर डीजल और पेट्रोल के साथ गिरफ्तार किया था।

इंस्पेक्टर दीनानाथ बने सचेंडी थाना प्रभारी

पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने बुधवार को इंस्पेक्टर दीनानाथ मिश्रा को सचेंडी थाने का प्रभार दे दिया। उनके पास गुजैनी थाने का चार्ज था। दीनानाथ मिश्रा को किशोरी के दुष्कर्म की घटना में निलंबित हुए इंस्पेक्टर विक्रम सिंह की जगह सचेंडी थाने का प्रभारी बनाया गया है। गुजैनी थाने का प्रभार जनशिकायत प्रकोष्ठ के इंस्पेक्टर राजन शर्मा को मिला है।

अतिक्रमणकारियों के आगे बेबस नजर आ रहा है जिला प्रशासन

सुल्तानपुर। जिला प्रशासन अतिक्रमणकारियों के आगे बेबस नजर आ रहा है लगभग 1 माह से अधिक समय से नगर पालिका द्वारा लाउडस्पीकर के माध्यम से आक्रमणकारियों को आवागमन के लिए रास्ता मुक्त करने का आवाहन किया जा रहा है लेकिन दबंग आक्रमणकारी उसको नजर अंदाज कर अपने जगह पर कायम है वहीं जिला प्रशासन भी कई दिनों से अतिक्रमण विरोधी अभियान चला रहा है लेकिन अभियान का दस्ता ज्यों ही आगे बढ़ता है पीछे से आक्रमणकारी फिर अपनी जगह पर काबिज हो जाते हैं इन लोगों को न तो चालान का डर है और न ही अपने सामान को जप्त होने का, कारण है कि जैसे ही आक्रमण विरोधी अभियान निकलता है वैसे ही इन्हें पहले से ही सूचना हो जाती है और रास्ते से अपना सामान हटा लेते हैं और दस्ते के आगे बढ़ते ही फिर से उनकी दुकानें सज जाती हैं।

प्रदेश की पहचान और सामर्थ्य का वैश्विक मंच बनेगा यूपी दिवस': सीएम योगी

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की स्थापना की स्मृति में आयोजित होने वाला उत्तर प्रदेश दिवस-2026 इस वर्ष और अधिक व्यापक, भव्य एवं वैश्विक स्वरूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि 24 से 26 जनवरी तक प्रस्तावित तीन दिवसीय समारोह के अंतर्गत राजधानी लखनऊ में मुख्य आयोजन के साथ-साथ प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों, देश के सभी राजभवनों तथा विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी यूपी दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

गुरुवार को तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के नागरिक आज देश-दुनिया के अनेक हिस्सों में अपनी पहचान बना चुके हैं। यूपी दिवस ऐसा अवसर बने, जो प्रवासी उत्तर प्रदेशवासियों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े। इसके लिए सभी राजभवनों में संवाद स्थापित कर आयोजन सुनिश्चित किए जाएं। इन आयोजनों में प्रदेश सरकार के मंत्री उपस्थित रहकर प्रवासी यूपीवासियों से संवाद करेंगे।

मुख्यमंत्री ने विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भी यूपी दिवस आयोजन के लिए संवाद बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'यूपी दिवस' केवल एक औपचारिक उत्सव नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक चेतना, आर्थिक शक्ति और विकास यात्रा को वैश्विक मंच पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का माध्यम है। आयोजन गरिमामय, सुव्यवस्थित, नवाचारयुक्त और व्यापक जनभागीदारी से युक्त हों। उन्होने जिला, मंडल और राज्य स्तर पर गायन, नृत्य, वादन और नाट्य प्रतियोगिताओं के आयोजन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि जनपद स्तरीय समारोहों में जिले की विकास यात्रा पर केंद्रित विशेष फ़िल्म भी प्रदर्शित की जाये।यूपी दिवस के अवसर पर 'उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान', 'विश्वकर्मा श्रम सम्मान' और 'माटी कला बोर्ड सम्मान' प्रदान किए जाएंगे। उद्यमियों, खिलाड़ियों, महिलाओं, चिकित्सकों, वैज्ञानिकों और प्रगतिशील किसानों को सम्मानित कर प्रदेश की प्रतिभा और परिश्रम को सम्मान दिया जाएगा। इसके साथ ही, प्रदेश की ऐतिहासिक और वैचारिक विरासत को जनमानस से जोड़ने के लिए धरती आबा बिरसा मुंडा, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, सरदार वल्लभभाई पटेल, वंदे मातरम्-आनंद मठ और पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होल्कर से जुड़े नाट्य मंचनों का आयोजन किया जाएगा। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा वंदे मातरम् रचना के 150 वर्ष पूर्ण होने पर आनंद मठ आधारित विशेष प्रस्तुति होगी। युवाओं और विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्र वंदे मातरम्' तथा विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश' थीम पर नृत्य-नाटिकाएं प्रस्तुत करेंगे। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि इस वर्ष आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रदेश की संस्कृति को प्रस्तुत करते हुए 3-डी और फाइबर मॉडल, वर्चुअल रियलिटी, 360 डिग्री टूर, लघु फिल्में, क्विज प्रतियोगिताएं और छायाचित्र प्रदर्शनी आयोजित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'यूपी दिवस' को जनउत्सव का स्वरूप देने के लिए ओपन माइक, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली थियेटर, रंगोली, पारंपरिक परिधान प्रतियोगिता, पाक-कला प्रतियोगिता और कला ग्राम जैसे आयोजन होंगे। आगरा, किराना, बनारस, हरिहरपुर, लखनऊ और रामपुर, हरिहरपुर और बदायूं जैसे प्रतिष्ठित संगीत घरानों की विशेष प्रस्तुतियां भी होंगी।

योगी सरकार की अप्रेंटिसशिप से युवाओं के लिए खुल रहे नौकरी के द्वार

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में युवाओं के कौशल विकास और रोजगारपरक प्रशिक्षण को नई रफ्तार देने के लिए योगी सरकार ने अप्रेंटिसशिप के क्षेत्र में मजबूत पहल की है। राज्य में संचालित अप्रेंटिसशिप योजनाओं के माध्यम से बड़ी संख्या में युवाओं को उद्योगों व एमएसएमई इकाइयों से जोड़ा जा रहा है, ताकि उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण के साथ रोजगार के अवसर भी मिल सकें।

वर्ष 2025-26 में अप्रेंटिसशिप योजना के तहत 83,277 युवाओं को उद्योगों और एमएसएमई इकाइयों में शिक्षुता प्रशिक्षण के लिये योजित किया गया है। इससे युवाओं को उत्पादन इकाइयों, सेवा क्षेत्र और लघु-मध्यम उद्योगों में काम सीखने का प्रत्यक्ष अवसर मिला है। सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक युवा ₹सीखते हुए कमाएं₹ और उद्योगों के अनुरूप कौशल प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनें। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिलदेव अग्रवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश को कुशल मानव संसाधन का हब बनाने का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। अप्रेंटिसशिप योजना के माध्यम से युवाओं को सिर्फ प्रमाण पत्र नहीं, बल्कि काम का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है।

हमारे लिए लक्ष्य केवल प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि प्रशिक्षित युवाओं को उद्योगों से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। नेशनल और मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजनाओं के तहत दी जा रही प्रतिपूर्ति से अधिष्ठानों की रुचि बढ़ी है और इससे रोजगारपरक अवसरों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। राज्य सरकार हर युवा को उसकी क्षमता के अनुरूप कौशल और अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश में नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना तथा मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत संबंधित अधिष्ठानों और अभ्यर्थियों को प्रतिपूर्ति की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। इससे शिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि के दौरान आर्थिक सहयोग मिलता है, वहीं अधिष्ठानों को भी प्रशिक्षुओं को रखने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होता है। योगी सरकार का मानना है कि यह मॉडल युवाओं और उद्योग दोनों के लिए लाभकारी है। अप्रेंटिसशिप के दायरे को बढ़ाने के लिए सशक्त संस्थागत ढांचा तैयार किया गया है। इसी के परिणामस्वरूप पिछले चार वर्षों में 795 नवीन अधिष्ठानों को पोर्टल पर पंजीकृत कराया गया है। नए पंजीकरण से विभिन्न जिलों में प्रशिक्षण के अवसरों का दायरा बढ़ा है और स्थानीय स्तर पर युवाओं को उद्योगों तक पहुंच आसान हुई है।

माघ मेला 2026 में श्रद्धालुओं की सुविधा को नई ऊँचाई, चार पर्यटन सूचना केंद्रों से 20 लाख से अधिक लोग लाभान्वित

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी विजन और मार्गदर्शन में संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेला 2026 का शुभारंभ 3 जनवरी से भव्य और दिव्य स्वरूप में हो चुका है। आस्था, सुविधा और सुव्यवस्था के संगम के रूप में विकसित हो रहा यह मेला अब केवल धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सांस्कृतिक और पर्यटन दृष्टि से भी देश-दुनिया में नई पहचान बना रहा है। करोड़ों श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए योगी सरकार द्वारा व्यापक, प्रभावी और आधुनिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।इसी क्रम में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा प्रयागराज के प्रमुख स्थलों पर चार अस्थायी पर्यटन सूचना केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। 3 जनवरी से अब तक इन सूचना केंद्रों के माध्यम से करीब 20 लाख से अधिक श्रद्धालु और पर्यटक लाभान्वित हो चुके हैं। इस वर्ष माघ मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के प्रयागराज आगमन का अनुमान है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार पर्यटकों और श्रद्धालुओं को सही, सरल और सटीक जानकारी उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है।अस्थायी पर्यटन सूचना केंद्रों पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रयागराज के प्रमुख पर्यटन स्थलों से संबंधित विस्तृत जानकारी वाली पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके साथ ही गाइड बुक, प्रशिक्षित टूरिस्ट गाइड की सूची और शहर भ्रमण से जुड़ी आवश्यक जानकारियां भी उपलब्ध हैं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और संतुष्टि को केंद्र में रखकर कार्य कर रही है। इसी सोच के तहत पर्यटन सूचना केंद्रों पर पंजीकृत पेइंग गेस्ट हाउस, धर्मशाला और अन्य ठहरने के विकल्पों की जानकारी भी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही है।इन सूचना केंद्रों पर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से माघ मेले से जुड़ी व्यवस्थाओं, सुरक्षा प्रबंधों, स्वच्छता अभियानों और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आधारित वीडियो भी प्रदर्शित किए जा रहे हैं। साथ ही विस्तृत सेक्टर मैप लगाए गए हैं, जिससे श्रद्धालु आसानी से यह जान सकें कि किस सेक्टर में कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं और वहां तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग कौन सा है।

मोदी सरकार ने 11 वर्षों में ग्रामीण भारत की दशा और दिशा बदली, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए : पंकज चौधरी

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने गुरुवार को वाराणसी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने बीते 11 वर्षों में ग्रामीण भारत की दशा और दिशा दोनों को ऐतिहासिक रूप से बदल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों, पारदर्शी व्यवस्था और गरीब-कल्याण के संकल्प का ही परिणाम है कि देश में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, जो अपने आप में एक बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि है।प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार का उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि गरीब, वंचित, जनजाति और पिछड़े वर्ग के श्रमिकों को सम्मानजनक आजीविका और गरिमा प्रदान करना है। विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का एक नया ढांचा तैयार किया गया है, जो महात्मा गांधी की भावना से प्रेरित है और राम राज्य की अवधारणा को साकार करने की दिशा में एक ठोस कदम है। उन्होंने कहा कि गांव, गरीब और किसान को केंद्र में रखकर बनाई गई नीतियों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती दी है।पंकज चौधरी ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर तीखा हमला करते हुए कहा कि आखिर विकसित भारत और भगवान राम के नाम से इन्हें इतनी नफरत क्यों है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस चाहे कितनी भी साजिशें रच ले, देश 2047 तक विकसित भारत बनकर रहेगा और इस लक्ष्य को कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि जनता अब झूठे नारों और भ्रम की राजनीति को पहचान चुकी है।प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी दी कि नई ग्रामीण रोजगार व्यवस्था के तहत हर ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। वन क्षेत्रों में कार्य करने वाले अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों को अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि काम के दिन बढ़ने के साथ-साथ मजदूरी भुगतान की व्यवस्था भी अधिक तेज और पारदर्शी होगी। साप्ताहिक भुगतान का प्रावधान किया गया है, जबकि पहले मनरेगा में मजदूरी 15 दिन में मिलती थी, जिससे श्रमिकों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।उन्होंने कहा कि मनरेगा पर सबसे अधिक खर्च मोदी सरकार के कार्यकाल में हुआ है। अब तक इस योजना पर कुल 11.74 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जिनमें से 8.53 लाख करोड़ रुपये केवल मोदी सरकार ने दिए हैं। पंकज चौधरी ने कहा कि ये आंकड़े कांग्रेस के झूठे और भ्रामक दावों की पोल खोलने के लिए पर्याप्त हैं।प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वर्ष 2005 में मनरेगा की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब ग्रामीण भारत की स्थिति और आवश्यकताएं पूरी तरह बदल चुकी हैं। वर्ष 2011-12 में जहां ग्रामीण गरीबी 25.7 प्रतिशत थी, वहीं 2023-24 में यह घटकर मात्र 4.86 प्रतिशत रह गई है। आज कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, आजीविका के नए साधन विकसित हुए हैं और गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। ऐसे में पुराने ओपन-एंडेड मॉडल को वर्तमान जरूरतों के अनुसार पुनर्गठित करना जरूरी हो गया था।उन्होंने यह भी कहा कि यूपीए सरकार के समय मनरेगा में पारदर्शिता का भारी अभाव था, जबकि नई व्यवस्था में रियल टाइम डेटा अपलोड, जीपीएस और मोबाइल मॉनिटरिंग तथा एआई आधारित फ्रॉड डिटेक्शन की व्यवस्था लागू की गई है। इससे भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लगेगी और वास्तविक लाभार्थियों को समय पर काम और भुगतान सुनिश्चित होगा।

बंद घरों की रेकी कर चोरी करने वाले तीन शातिर चोर गिरफ्तार, नकदी, मोबाइल और वाहन बरामद

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के उत्तरी जोन अंतर्गत थाना अलीगंज पुलिस ने बंद घरों और दुकानों की रेकी कर चोरी करने वाले तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 7,420 रुपये की नकदी, दो मोबाइल फोन, एक ड्राइविंग लाइसेंस तथा घटना में प्रयुक्त टाटा मोटर्स इंट्रा V30 वाहन बरामद किया है, जिसे सीज कर दिया गया है।पुलिस के अनुसार 7 जनवरी 2026 को मोहिबुल्लापुर थाना मड़ियांव निवासी आयुष यादव ने थाना अलीगंज में तहरीर दी थी कि वह एक दूध डेयरी में काम करता है, जहां से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा 12 हजार रुपये नकद और उसका ड्राइविंग लाइसेंस चोरी कर लिया गया। इस तहरीर के आधार पर थाना अलीगंज में मुकदमा संख्या 07/2026 धारा 305 और 331(4) बीएनएस के तहत अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।मामले के खुलासे के लिए थाना अलीगंज पुलिस टीम ने साक्ष्य संकलन और मुखबिर की सूचना के आधार पर 8 जनवरी 2026 को ईदगाह के पास कूड़ा डालने वाले मोड़ के पास से तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में शमद, सलीम और अरशद अली शामिल हैं, जो सभी थाना ठाकुरगंज क्षेत्र के निवासी हैं और जिनकी उम्र करीब 30 वर्ष बताई गई है।

पुलिस तलाशी के दौरान अभियुक्तों के कब्जे से 7,420 रुपये नकद, एक रेडमी 14C 5G मोबाइल, एक ओप्पो रेनो 2 मोबाइल तथा आयुष यादव के नाम का ड्राइविंग लाइसेंस बरामद हुआ।

आयुष्मान योजना में क्लेम निस्तारण में बड़ा सुधार, एक साल में पेंडेंसी 10 .75 लाख से घटकर 3 लाख, 4,649 करोड़ का भुगतान

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। योगी सरकार गरीबों और जरूरतमंदों को बेहतर, सुलभ और समयबद्ध स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जहां लाभार्थी परिवारों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिल रही है, वहीं योजना से जुड़े सरकारी और निजी अस्पतालों को समय पर भुगतान सुनिश्चित कर पूरी व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि बीते एक वर्ष में आयुष्मान योजना के अंतर्गत क्लेम निस्तारण की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।स्टेट एजेंसी फॉर कॉमप्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (साचीज) की सीईओ अर्चना वर्मा ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश के सूचीबद्ध अस्पतालों से प्राप्त होने वाले क्लेम के त्वरित और पारदर्शी निस्तारण के लिए लगातार सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जनवरी 2025 में क्लेम की पेंडेंसी जहां 10 लाख 75 हजार तक पहुंच गई थी, वहीं दिसंबर 2025 तक इसे घटाकर मात्र 3 लाख कर दिया गया है, जिसे भी शीघ्र ही निस्तारित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर माह औसतन 2 लाख से अधिक क्लेम प्राप्त होते हैं। इतनी बड़ी संख्या में आने वाले क्लेम का समयबद्ध निस्तारण एक बड़ी चुनौती है, इसके बावजूद यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पुराने लंबित मामलों के साथ-साथ नए क्लेम का भी नियमित और व्यवस्थित ढंग से निस्तारण हो, ताकि अस्पताल बिना किसी हीलाहवाली के आयुष्मान कार्डधारकों का इलाज जारी रखें।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर क्लेम निस्तारण प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए मेडिकल ऑडिट व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया गया है। साचीज की एसीईओ पूजा यादव ने बताया कि मेडिकल ऑडिटरों की संख्या 40 से बढ़ाकर 130 कर दी गई है, जिससे क्लेम की जांच प्रक्रिया में तेजी आई है। इसके साथ ही क्लेम प्रोसेसिंग डेस्क की संख्या भी 100 से बढ़ाकर 125 कर दी गई है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत अस्पतालों द्वारा प्रस्तुत क्लेम का भुगतान 30 दिनों की निर्धारित समय-सीमा, यानी टर्न अराउंड टाइम के भीतर सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एजेंसी स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकें की जा रही हैं और लंबित मामलों की लगातार निगरानी की जा रही है।साचीज की सीईओ अर्चना वर्मा ने बताया कि जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 की अवधि के दौरान आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रदेश के सूचीबद्ध अस्पतालों को क्लेम के सापेक्ष कुल 4,649 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि योगी सरकार न केवल गरीबों के इलाज की गारंटी दे रही है, बल्कि अस्पतालों के आर्थिक हितों की भी पूरी तरह से रक्षा कर रही है।

आदिवासियों की आवाज दबाने के लिए झूठे मुकदमे और गिरफ्तारी, लोकतंत्र पर सीधा हमला : श्याम लाल पाल

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने भाकपा माले लिबरेशन के उत्तर प्रदेश राज्य सचिव कामरेड सुधाकर यादव और मिर्जापुर की जिला सचिव कामरेड जीरा भारती की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि प्रशासन और वन विभाग चार पीढ़ियों से बसे गरीब आदिवासी परिवारों को जबरन बेदखल करने की कार्रवाई कर रहे हैं और इसके खिलाफ आवाज उठाने वालों को झूठे मुकदमों में फंसाकर उत्पीड़ित किया जा रहा है। विरोध करने पर नेताओं और कार्यकर्ताओं पर गंभीर धाराएं लगाना पूरी तरह अन्यायपूर्ण और तानाशाही मानसिकता को दर्शाता है।श्याम लाल पाल ने कहा कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद पुलिस गाड़ी में बूट से मारपीट और जेल के भीतर भी उत्पीड़न की खबरें अत्यंत शर्मनाक और निंदनीय हैं। गांव के गरीबों के घरों और खेतों पर बुलडोजर चलाना तथा आंदोलन का नेतृत्व करने वालों को निशाना बनाना सत्ता के दुरुपयोग का स्पष्ट उदाहरण है। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीबों और आदिवासियों को डराने के लिए प्रशासनिक ताकत का खुला इस्तेमाल किया जा रहा है।उन्होंने बताया कि मिर्जापुर जनपद के लालगंज थाना क्षेत्र के तेंदुआ खुर्द गांव में वन विभाग और प्रशासन की मिलीभगत से आदिवासी परिवारों को बेदखल करने के लिए रात के अंधेरे में जेसीबी मशीनें लगाई गईं। लहलहाती फसलों को रौंद दिया गया और महिलाओं व लड़कियों के साथ अभद्रता की गई। हैरानी की बात यह है कि जिस समय यह पूरी कार्रवाई हो रही थी, उस समय कामरेड सुधाकर यादव और जीरा भारती मौके पर मौजूद भी नहीं थे, इसके बावजूद उनके खिलाफ हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराएं लगा दी गईं।

ग्रामीण विकास में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गांवों के विकास कार्यों को तेज़ी से धरातल पर उतारने के उद्देश्य से ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को व्यापक और सख़्त दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इस लक्ष्य की प्राप्ति में किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। उप मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि सभी विकास कार्य समयबद्ध ढंग से पूर्ण किए जाएं और गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। साथ ही योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचे, इसके लिए नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गुरुवार को अपने कैंप कार्यालय, 7 कालिदास मार्ग पर आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में ग्राम्य विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि प्रत्येक शुक्रवार को प्रत्येक विकास खंड की दो ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए ग्राम चौपालों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि इन चौपालों को सुव्यवस्थित, सुचारू और व्यापक स्तर पर आयोजित किया जाए, ताकि गांव में ही लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। साथ ही ग्राम चौपालों के माध्यम से "विकसित भारत–जी राम जी" अधिनियम के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के महत्व और उद्देश्य को जन-जन तक पहुंचाने की प्रबल आवश्यकता है, इसके लिए पंपलेट वितरित किए जाएं और स्वयं सहायता समूहों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाए। उप मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि विभाग से किसी भी स्तर पर भेजे जाने वाले पत्रों पर समयबद्ध कार्यवाही अनिवार्य रूप से की जाए।बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार सृजन के लिए 'विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' अधिनियम–2025 पारित किया गया है। सरकार की मंशा है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को समय पर काम मिले, प्रत्येक गांव में टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण हो और प्रत्येक श्रमिक को सम्मान, सुरक्षा और खुशहाली प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम ग्रामीण विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। प्रदेश सरकार इसे पूरी संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ लागू कर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की नई गारंटी प्रदान करेगी। इस अधिनियम के तहत रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन की गई है, श्रमिकों के पारिश्रमिक भुगतान की व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाया गया है, जबकि किसानों को बुआई और कटाई के समय मजदूरों की कमी से राहत देने के लिए राज्यों को 60 दिन तक कार्य विराम का अधिकार भी दिया गया है।उप मुख्यमंत्री ने दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान के प्रशिक्षण कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि संस्थान की प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाई जाए और सभी चयनित प्रशिक्षणार्थियों को पूरी क्षमता के साथ प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि आजीविका मिशन से संबंधित सभी प्रशिक्षण एसआईआरडी में ही कराए जाएं। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा सभी प्रशिक्षणार्थियों को नामित कर एक सप्ताह के भीतर सूची उपलब्ध कराई जाए और प्रशिक्षण के दौरान बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज की जाए। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि सरकार की मंशा और भावना को समझते हुए पूरी निष्ठा, ईमानदारी और गंभीरता के साथ विकास कार्यों को अमल में लाया जाए, ताकि कार्यों का असर साफ तौर पर धरातल पर दिखाई दे।उप मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि महिलाओं को हर हाल में सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। जहां भी प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, वहां महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें दक्ष और सक्षम बनाया जाए। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में जिला प्रशिक्षण केंद्रों के अपने भवन नहीं हैं, वहां विभागीय भवनों के निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार कर बजट का प्रावधान कराया जाए। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता और मानकों का विशेष ध्यान रखा जाए तथा बजट का समय पर उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि ग्राम्य विकास विभाग के पीडीएस संवर्ग और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी दीदियों को मिशन कर्मयोगी के तहत प्रशिक्षण दिलाया जाए।बैठक में उप मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग और स्पर्श प्रणाली के अधिकारियों के साथ भुगतान प्रक्रिया को लेकर चर्चा की और ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपसी समन्वय स्थापित कर भुगतान प्रक्रिया को तेज किया जाए। उन्होंने कहा कि योजना बनाकर समयबद्ध रूप से भुगतान सुनिश्चित किया जाए। समूह सखियों को अधिक सक्रिय करने, उन्हें समय पर देय धनराशि उपलब्ध कराने, निष्क्रिय समूहों को सक्रिय करने और अधिक से अधिक नए समूह बनाने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि आजीविका मिशन में फील्ड स्तर पर मैनपावर की समस्या को शीघ्र दूर किया जाए। सरकार का लक्ष्य है कि तीन करोड़ दीदियों को समूहों से जोड़ा जाए और एक करोड़ दीदियों को हर हाल में लखपति दीदी बनाया जाए।उप मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों और पीएमजीएसवाई सड़कों की समीक्षा करते हुए कहा कि जो ठेकेदार अनावश्यक रूप से कार्यों में देरी कर रहे हैं या रुचि नहीं ले रहे हैं, उनके खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए, जबकि अच्छा कार्य करने वाले ठेकेदारों का अभिनंदन किया जाए। उन्होंने ठेकेदारों की बैठक बुलाने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही राष्ट्रीय एकीकरण विभाग को नवाचार आधारित योजनाओं की प्लानिंग करने और सार्वजनिक उद्यम विभाग को विभागीय परिसंपत्तियों का विस्तृत आकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।बैठक में राज्य मंत्री ग्राम्य विकास विभाग विजयलक्ष्मी गौतम ने भी महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। बैठक में अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग बी एल मीणा, महानिदेशक दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान एल वेंकटेश्वर लू, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास विभाग सौरभ बाबू, आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग गौरी शंकर प्रियदर्शी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की मिशन निदेशक दीपा

उम्मीद-ए-सहर की बात सुनो!

नई सुबह और नई उम्मीदों के साथ नए साल का स्वागत है। बीता हुआ साल अच्छा नहीं था। अप्रैल में पहलगाम में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों के 25 बेकसूर सैलानियों और एक स्थानीय कश्मीर व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई में 'ऑपरेशन सिंदूर' के जरिए छह और सात मई की दरम्यानी रात को आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया लेकिन दुर्भाग्य से यह ऑपरेशन पाकिस्तान के साथ सीमित युद्ध में बदल गया। पहले के बालाकोट या उरी स्ट्राइक से उलट पाकिस्तान ने जवाबी हमला कर दिया। इसका अंत 10 नवंबर को बिल्कुल अप्रत्याशित तरीके से हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान किया। उसके बाद से वे करीब एक सौ बार कह चुके हैं कि उन्होंने व्यापार बंद करने और टैरिफ बढ़ाने का दबाव डाल कर भारत और पाकिस्तान को सीजफायर के लिए तैयार कराया। इसके बाद साल के अंत में राजधानी दिल्ली में लाल किले के सामने कार बम धमाका हुआ, जिसमें एक दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए। इन दो घटनाओं ने सरकार के बनाए सुरक्षा नैरेटिव को पूरी तरह से बदल दिया।

जुलाई का महीना एक अलग स्ट्राइक लेकर आया, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका जाने वाले भारत के उत्पादों पर पर 25 फीसदी का टैरिफ लगाया और रूस से तेल खरीदने की सजा देते हुए 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगाया। इसके बाद से भारतीय मुद्रा यानी रुपए में गिरावट का ऐसा सिलसिला चला है कि एक डॉलर 90 रुपए से ज्यादा का हो गया है। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में पूरी तरह से भारत विरोधी माहौल बन गया है, जिसका फायदा पाकिस्तान और चीन दोनों उठा रही हैं। शेख हसीना के तख्तापलट और उनके भारत आने के बाद से हिंदुओं पर हो रहे हमलों में पिछले साल अचानक तेजी आई। हिंदुओं पर हमले की दर्जनों घटनाएं हुई हैं और दिसंबर 2025 के आखिरी 15 दिन में तीन हत्याएं हुईं। वहां हालात 1971 जैसे बन रहे हैं और उसी तरह शरणार्थियों के भारत की सीमा पर जमा होने की आशंका बन गई है। नेपाल में भी सत्ता परिवर्तन हुआ और केपी शर्मा ओली का तख्तापलट करा कर जेन जी ने सुशीला कार्की को सत्ता सौंपी। एक तरह से पूरा साल भारत के लिए सामरिक नीति, कूटनीति और अर्थनीति तीनों में नैरेटिव गंवाने का रहा। दुनिया निश्चित रूप से दुविधा में रही कि 'ऑपरेशन सिंदूर' में सचमुच क्या हुआ था? उधर पाकिस्तान ने दुनिया की तीनों महाशक्तियों अमेरिका, रूस और चीन का सद्भाव हासिल किया। उसके सेना प्रमुख का व्हाइट हाउस में स्वागत हुआ।

अगर घरेलू राजनीति की बात करें तो सरकार का विपक्ष के साथ टकराव बढ़ता गया है। 2024 में लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद भाजपा की जीत का जो सिलसिला हरियाणा, महाराष्ट्र में बना वह 2025 में दिल्ली और बिहार में जारी रहा। लेकिन लगातार जीत के बावजूद भाजपा का शीर्ष नेतृत्व लोकसभा में बहुमत गंवाने के बाद से सहज नहीं हो पाया है। मुख्य विपक्षी पार्टी ने 'वोट चोरी' को ऐसा मुद्दा बनाया है, जिससे देश की पूरी चुनाव प्रक्रिया संदेह के घेरे में आई है। दुर्भाग्य की बात है कि चुनाव आयोग लोगों का संशय दूर करने की बजाय विपक्ष के विरोधी की तरह बरताव कर रहा है। विपक्ष की दूसरी पार्टियां 'वोट चोरी' के मामले में भले कांग्रेस के साथ पूरी तरह से सहमत नहीं हैं लेकिन संसद में चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान सबने चुनाव आयोग के पक्षपात का मुद्दा बनाया। चुनाव प्रक्रिया पर बन रहा अविश्वास अंततः लोकतंत्र को कमजोर करेगा। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर एक सही कदम है लेकिन इसे जिस तरह से जल्दबाजी में लागू किया गया उससे संदेह पैदा हुआ है। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हुई एसआईआर की प्रक्रिया में कई तरह की कमियां सामने आई हैं। भारत में राजनीति का विभाजन जितना गहरा हुआ है उसी अनुपात में समाज का विभाजन भी बढ़ा है। यह सामाजिक विभाजन लंबे समय में भारत की एकता और अखंडता को प्रभावित करने वाला होगा।

सो, नए साल में गालिब की तरह यह तो नहीं कह सकते हैं कि, 'एक बिरहमन ने कहा है कि ये साल अच्छा है', लेकिन फैज की तरह 'सहर की बात उम्मीद-ए-सहर की बात' यानी कर सकते हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक होगा। भारत ने ब्रिटेन से लेकर न्यूजीलैंड कर सात देशों के साथ मुक्त व्यापार संधि की है और उम्मीद है कि नए साल में जनवरी या फरवरी में अमेरिका के साथ व्यापार संधि हो जाएगी। अमेरिका के साथ व्यापार संधि से बहुत कुछ बदलेगा। भारत का अलगाव समाप्त होगा। टैरिफ कम होगा, जिससे निर्यात बढ़ेगा और आर्थिकी पर दबाव कम होगा। यूरोपीय संघ के साथ भी भारत की व्यापार वार्ता अंतिम चरण में है। इससे भारत की आर्थिकी में एक ठहराव आने की उम्मीद है।

सिखों के दशम गुरु — गुरु गोविंद सिंह

ऐसे महान योद्धा और गुरु का जन्म मुग़ल शासन के समय पौष शुदी सप्तमी संवत 1723 (तदनुसार 22 दिसम्बर, 1666) को पटना शहर में गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के घर हुआ।

अशोक प्रवृद्ध

उन्होंने देश, धर्म और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सिखों को संगठित किया और उन्हें सैनिक परिवेश में ढाला। मान्यता है कि धर्म और न्याय की प्रतिष्ठा के लिए गुरु गोविंद सिंह का अवतरण हुआ था। इसी उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था — मुझे परमेश्वर ने दुष्टों का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए भेजा है।

5 जनवरी – गुरु गोविंद सिंह जयंती

सिख धर्म के सर्वाधिक वीर योद्धा और निर्बलों को अमृतपान कर शस्त्रधारी बनाकर उनमें वीर रस भरने वाले सिख समुदाय के दसवें और अंतिम धर्मगुरु (सतगुरु) गुरु गोविंद सिंह (22 दिसम्बर, 1666 ई. — पटना, बिहार; 7 अक्टूबर, 1708 ई. — नांदेड़, महाराष्ट्र) न केवल सिखों के सैनिक संगति और ख़ालसा के सृजन के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि वे उस ऐतिहासिक निर्णय के लिए भी लोकप्रसिद्ध हैं कि अब सिख पंथ में देहधारी गुरु की परंपरा समाप्त हो और गुरु ग्रंथ साहिब ही सर्वमान्य गुरु हो। गुरु गोविंद सिंह ने सर्वप्रथम खालसा पंथ में सिंह उपनाम लगाने की शुरुआत की। उन्होंने आदेश दिया कि आगे से कोई भी देहधारी गुरु नहीं होगा — गुरु की वाणी और गुरु ग्रंथ साहिब ही सिखों के लिए गुरु की भूमिका रखेंगे। एक प्रवीण कवि के रूप में गुरु गोविंद सिंह ने समय के अनुकूल योगियों, पंडितों और संतों के लिए बाणी की रचना की, जिसे बाद में बेअंत बाणी कहा गया।

ऐसे महान योद्धा और गुरु का जन्म मुग़ल शासन के समय पौष शुदी सप्तमी संवत 1723 (तदनुसार 22 दिसम्बर, 1666) को पटना शहर में गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के घर हुआ। उनका नाम गोविंद राय रखा गया। उनके जन्म पर पूरे शहर में उत्सव मनाया गया। बचपन में गोविंद को खिलौनों से खेलना पसंद था, लेकिन वे तलवार, कृपाण, धनुष बाण से खेलने में भी रुचि रखते थे। बाल्यकाल से ही वे अत्यंत शरारती थे, परन्तु दूसरों को कष्ट नहीं देते थे। एक किस्सा प्रसिद्ध है कि वे सूत काटने वाली एक निसंतान वृद्धा के साथ शरारत करते थे — उसकी सूत की पूनियाँ बिखेर देते थे। जब वृद्धा उनके माता पिता के पास शिकायत लेकर जाती थी, तो माता गुजरी पैसे देकर उसे खुश कर देती थीं। एक बार माता गुजरी ने गोविंद से कारण पूछा कि तुम वृद्धा को तंग क्यों करते हो? गोविंद ने सहज भाव से कहा कि वह उसकी गरीबी दूर करना चाहता है — क्योंकि अगर मैं उसे परेशान नहीं करूंगा, तो उसे पैसे कैसे मिलेंगे? गोविंद राय को सैन्य जीवन का लगाव अपने दादा गुरु हरगोबिन्द सिंह से मिला था और उन्हें महान बौद्धिक संपदा भी विरासत में मिली थी। बहुभाषाविद गुरु गोविंद सिंह को फ़ारसी, अरबी, संस्कृत और पंजाबी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। उन्होंने सिख क़ानून को सूत्रबद्ध किया, काव्य रचना की, और सिख ग्रंथ दसम ग्रंथ (दसवाँ खंड) लिखकर प्रसिद्धि पाई।

उन्होंने देश, धर्म और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सिखों को संगठित किया और उन्हें सैनिक परिवेश में ढाला। मान्यता है कि धर्म और न्याय की प्रतिष्ठा के लिए गुरु गोविंद सिंह का अवतरण हुआ था। इसी उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था — मुझे परमेश्वर ने दुष्टों का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए भेजा है। यही कारण है कि आज भी गुरु गोविंद सिंह के जन्म उत्सव को गुरु गोविंद जयंती के रूप में श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर गुरुद्वारों में भव्य कार्यक्रमों के साथ गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता है और अंत में सामूहिक भंडारा यानी लंगर का आयोजन होता है। नवीन मत के अनुसार 2026 में गुरु गोविंद सिंह जयंती 5 जनवरी को मनाई जाएगी। खालसा पंथ में विशेष महत्त्व रखने वाले इस अवसर पर उनके जन्म स्थल पटना साहिब तथा आनंदपुर साहिब (गुरुद्वारा केशगढ़ साहिब) और अन्य स्थानों पर जयंती अत्यधिक धूमधाम से मनाई जाती है।

अपने पिता गुरु तेग बहादुर की बलिदान के बाद, जब वे केवल 9 वर्ष के थे, तो बालक गोविंद राय को गुरु गद्दी संभालनी पड़ी। गुरु की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्होंने अपना ज्ञान बढ़ाया और संस्कृत, फ़ारसी, पंजाबी और अरबी भाषाएँ सीखीं। उन्होंने धनुष बाण, तलवार, भाला आदि हथियार चलाने की कला भी सीखी। उन्होंने अन्य सिखों को भी अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया। सिखों को अपने धर्म, जन्मभूमि और अपनी रक्षा के लिए संकल्पबद्ध किया और उन्हें मानवता का पाठ पढ़ाया। उनका नारा था — सत श्री अकाल। जाति भेद और सम्प्रदायवाद को जड़ से समाप्त करने हेतु गुरु गोविंद सिंह ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। देश के अलग अलग भागों तथा समाज के विभिन्न जातियों और सम्प्रदायों से आए पांच प्यारे — जिन्हें पंच प्यारे के नाम से जाना जाता है — को एक ही कटोरे में अमृत पिला कर एक किया गया। इस क्रांति के बीज से उन्होंने जाति भेद तथा सम्प्रदायवाद को मिटाया। परंपरा के अनुसार, पंजाब में फ़सल की कटाई पहली बैसाख को ही शुरू होती है और देश के अन्य हिस्सों में भी इसी दिन फ़सल कटाई का त्योहार मनाया जाता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि बैसाखी दिवस को गुरु गोविंद सिंह के जीवन के आदर्शों को देश, समाज और मानवता की भलाई के लिए प्रेरणा मानकर श्रद्धापूर्वक मनाने से आतंकवाद तथा हमलावरों का सामना किया जा सकता है। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों में युद्ध की भावना तथा जीवन का उत्साह बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए। उन्होंने वीर काव्य और संगीत का सृजन किया और सिखों में लौह कृपा अर्थात कृपाण के प्रति प्रेम विकसित किया। खालसा को पुनः संगठित सिख सेना का मार्गदर्शक बनाकर उन्होंने दो मोर्चों पर शत्रुओं के खिलाफ क़दम उठाए — पहला मुग़लों के खिलाफ फ़ौज, और दूसरा विरोधी पहाड़ी जनजातियों के खिलाफ युद्ध। उनकी सैन्य टुकड़ियाँ सिख आदर्शों के प्रति पूरी तरह समर्पित थीं और सिखों की धार्मिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थीं। लेकिन गुरु गोविंद सिंह को इस स्वतंत्रता की भारी कीमत चुकानी पड़ी। अंबाला के पास एक युद्ध में उनके चारों बेटे मारे गए। गुरु गोविंद सिंह ने धर्म, संस्कृति एवं राष्ट्र की आन बान शान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनके सामने पहाड़ी राजाओं की ईर्ष्या पहाड़ जैसी ऊँची थी। दूसरी ओर औरंगज़ेब की धार्मिक कट्टरता की आँधी लोगों के अस्तित्व को लील रही थी। ऐसे समय में गुरु गोविंद सिंह ने समाज को एक नया दर्शन दिया। उन्होंने आध्यात्मिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए तलवार धारण की। गौरतलब है कि गुरु गोविंद सिंह और मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वु मित्र भी थे। गुरु जी ने अपने सैनिकों के साथ जांजू की लड़ाई में बहादुर शाह का साथ दिया, जिससे 8 जून 1707 को आगरा के पास बहादुर शाह की विजय हुई। प्रसन्न होकर बादशाह ने गुरु जी को आगरा बुलाया और उन्हें एक बड़ी कीमती सीरोपायो (सम्मान के वस्त्र) तथा एक धुकधुकी (गर्दन का गहना) भेंट की, जिसकी कीमत लगभग 60,000 रुपये थी। मुगल सरकार के साथ एक पुराने मतभेद का समाधान संभव दिखाई दे रहा था। इसी बातचीत के दौरान बहादुर शाह ने कछवाहा राजपूतों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु दक्षिण की ओर कूच किया। उनके भाई कामबख़्श ने बग़ावत कर दी। बग़ावत दबाने हेतु बादशाह दक्षिण की ओर चला गया और गुरु जी को भी साथ ले गया। इस सम्पूर्ण घटनाक्रम में गुरु जी का संघर्षरत रहना उनके महान कर्मयोगी होने का प्रमाण है। उन्होंने खालसा का मार्ग देश की अस्मिता, भारतीय विरासत और जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए अपनाया। वे सभी प्राणियों को आध्यात्मिक स्तर पर परमात्मा का ही रूप मानते थे। धर्म और समाज की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ई. में शुद्ध, निर्मल और बिना किसी मिलावट वाले व्यक्तियों का समूह बनाया, जिसे खालसा कहा गया। प्रत्येक परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण करते हुए स्वकर्म को स्वधर्म मानकर जुल्म और जालिम से लोहा लेने के लिए तत्पर खालसा हमारी मर्यादा और भारतीय संस्कृति की पहचान है।

टिप्पणी

राम भरोसे जीने विवश हो जाएंगे

मनरेगा के जी राम जी में बदलने से निवेशकों और धनी इलाकों के किसानों को सस्ती दर पर मजदूर मिल सकेंगे। मनरेगा से इसमें बाधा आई थी और यह इन तबकों की इस कानून से आरंभ से ही एक बड़ी शिकायत थी।

मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम) को वीबी- जी राम जी (विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन- ग्रामीण) में बदलने के नरेंद्र मोदी सरकार के इरादे में नागरिकों के प्रति उसके नजरिये की झलक देखी जा सकती है। मनरेगा उस दौर में बना, जब तत्कालीन यूपीए-1 सरकार ने विकास की अधिकार आधारित अवधारणा को अपनाया था। समझ यह थी कि गरिमामय जिंदगी की न्यूनतम शर्तों को वैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता दी जाए और उन स्थितियों को हासिल करने की योजनाएं लागू की जाएं। इस रूप में उस दौर में बने कई कानून सामान्य कल्याण योजनाओं से अलग थे।

इसीलिए मनरेगा को मांग केंद्रित बनाया गया- यानी प्रावधान किया गया कि ग्रामीण इलाकों में अकुशलकर्मी जब कभी मांग करेंगे, कम-से-कम 100 दिन उन्हें काम मुहैया करना सरकार के लिए अनिवार्य होगा। इस काम में पारिश्रमिक भुगतान का पूरा खर्च केंद्र उठाएगा, जबकि सामग्रियां आदि जुटाने का खर्च राज्य सरकार के खजाने से आएगा। अब ये सारे प्रावधान अब बदल जाएंगे। अब कुछ छोटे राज्यों को छोड़ कर बाकी हर राज्य की सरकार को पारिश्रमिक का 40 फीसदी हिस्सा भी अपने कोष से देना होगा। इसके अलावा योजना मांग केंद्रित नहीं रह जाएगी। जी राम जी बजट का उपयोग सरकार की प्राथमिकता से होगा। बोलचाल की आर्थिक भाषा में कहें, तो डिमांड साइड के बजाय सप्लाई साइड की योजना बन जाएगी।

फिर यह सालों भर चलने वाली योजना नहीं रहेगी। कृषि सीजन में इसे रोक दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर बदलाव सिर्फ नाम में नहीं, बल्कि अधिनियम के मूल ढांचे में है। नतीजा यह होगा कि आपातकाल में न्यूनतम रोजगार की आश्वस्ति प्रदान करने और मजदूरों का पलायन रोकने में मनरेगा का, भले ही न्यूनतम मगर जो महत्त्वपूर्ण योगदान बना, वह स्थिति अब नहीं रहेगी। इससे निवेशकों और कृषि सीजन में धनी इलाकों के किसानों को सस्ती दरों पर मजदूर मिल सकेंगे। मनरेगा से इसमें रुकावट आई थी और यह इन तबकों की इस कानून से आरंभ से एक बड़ी शिकायत थी। जबकि जिन गरीब मजदूरों का यह सहारा था, वे अब राम भरोसे जीने को अधिक विवश हो जाएंगे।

ब्लॉग

असल 'धुरंधर' अमेरिका

हरिशंकर व्यास

यह तारीफ़ नहीं है। वह सत्यमेव जयते है, जिसका आधार बुद्धि ज्ञान और सैन्य शक्ति, दोनों के एवरेस्ट की वाह है। अमेरिका ने सन् 2025-26 में दिमाग से कृत्रिम बुद्धि को स्थापित कर जहां मानवता को चमत्कृत किया, वहीं तीन जनवरी 2026 की रात में उसके सैन्य बल ने वेनेज़ुएला देश के राष्ट्रपति को उठा कर विश्व को चौंकाया। व्यर्थ है इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को 'धुरंधर बताना। असल सत्य ढाई सौ साल पुराने अमेरिका के उस संविधान, उस व्यवस्था का है, जिसमें असंभव को संभव बनाने का डीएनए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सांचे की धुन में निहित है। यह व्यवस्था की वह बुनावट है, जिसमें हर व्यक्ति असंभव को संभव बनाने के अवसर को खोजता है, लपकता है और उसमें अपने को खपाता है।

भारत में हम लोग व्यक्तियों, चेहरों यानी राष्ट्रपतियों, नेताओं को ताकते हैं, जबकि धुरंधरी व्यवस्था से बनती है। सिस्टम से उत्प्रेरित व्यक्तिगत मानसिकता, वृत्ति और आचरण से ही फिर अर्थ (पूंजीवाद, नवाचार, तकनीक, वित्तीय धुरी), काम (इच्छा, व्यक्तिगत भोग, उपभोक्तावाद, प्रतिस्पर्धा, जुनून, विलासिता) तथा धर्म की सार्वभौमिक, सेक्युलर समझ पैठती है। निश्चित ही खांटी अमेरिकी लोग परलोक, जन्म जन्मांतर या मोक्ष मुक्ति की धारणाओं में नहीं जीते हैं। वे वर्तमान के सत्य में जीते हैं। वहां के नागरिक अंधविश्वासों, टोने टोटकों, भक्ति और झूठ से लगभग मुक्त हैं। वे अतीत में नहीं, आधुनिकता में आगे बढ़ते जाने के लिए सतत हाथ पांव मारते हैं।

इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में भी वही है, जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा या राष्ट्रपति आइज़नहावर और उनके विदेश मंत्री जॉन फोस्टर डलेस के ₹डोनरो डॉक्ट्रिन₹ के शक्ति सूत्र में था। वेनेज़ुएला के ताज़ा प्रकरण में मुझे राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की कद काठी, भाव भंगिमा, बड़बोलेपन से बार बार सद्दाम हुसैन, कर्नल गद्दाफ़ी, ओसामा बिन लादेन, इस्लामिक स्टेट के बग़दादी आदि वे चेहरे याद होते हैं, जो कथित शक्ति, क्रूरता, बर्बरता के सूरमा भोपाली थे (इतिहास में एक नाम हिटलर भी है)। ये सब किसके शिकार हुए? अमेरिकी सैन्य ऑपरेशनों के। सही है कि इस काम में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपतियों की संख्या अधिक है, मगर डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपतियों ने भी संकोच नहीं किया। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ट्रंप के ताज़ा 'ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिज़ॉल्व की तरह ही 'ऑपरेशन नेप्च्यून स्पीयर को हरी झंडी दी थी। पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिका की नेवी सील टीम ने 9/11 हमलों के मास्टरमाइंड ओसामा को 1-2 मई 2011 की रात में मारने के ऑपरेशन को वैसे ही अंजाम दिया, जैसे इस तीन जनवरी की आधी रात को काराकास के राष्ट्रपति भवन में निकोलस मादुरो को दबोचने का सैन्य अभियान हुआ।

सो, ओबामा हों या डोनाल्ड ट्रंप, ये उस अमेरिकी व्यवस्था के प्रतिनिधि हैं, जिसमें ओलंपिक मेडल जीतना सामान्य बात है, तो सिलिकॉन वैली में कृत्रिम बुद्धि (एआई) की रचना का प्रतिमान भी सामान्य है; तो नौसेना की नेवी सील टीम हो या डेल्टा फ़ोर्स या सीआईए, सभी अपनी क्षमताओं का वह जज़्बा लिए होते हैं, जो वेयक्तिक धुन, टीम में पकती है और फिर बस उद्देश्य व कमांड की ज़रूरत होती है।

ऐसे जज़्बे वाले दूसरे देश का नाम इज़राइल है। इज़राइल की वजह यहूदियों का इतिहास बोध और संकल्प है। इज़राइल ने 1948 में गठन के बाद से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बूते ही अर्थ, धर्म, काम की मनुष्य वृत्तियों में नागरिकों और व्यवस्था को ऐसा बनाया है कि प्रधानमंत्री कोई हो, वह ज्ञात ख़तरों के प्रति कभी लापरवाह नहीं होता। इज़राइली व्यवस्था भी चेक बैलेंस में पाबंद है। नेतन्याहू हों या कोई प्रधानमंत्री, वे संस्थाओं और व्यवस्थाओं की स्वतंत्रता, जीवंतता का गला नहीं घोंटते। तभी ये दो ही देश हैं, जो विश्व राजनीति में बतौर धुरंधर बाकी सभी देशों को ठेंगा दिखाते हैं। ये जो चाहते हैं, वह करते हैं, फिर भले कोई इसे दादागीरी कहे या गुंडागर्दी!

सन् 2025 की जनवरी से इस तीन जनवरी की ताज़ा घटना में डोनाल्ड ट्रंप की पहचान मनमज़ीर् की है। इससे अमेरिकी पहचान बिगड़ी, तो अमेरिका में भी आर पार की राजनीति के पाले बने हैं। मगर अमेरिका के हित की कसौटी में गौर करें, तो ट्रंप के फैसले अर्थिकी, सैन्य क्षमता, उद्यमशीलता, सामाजिक संरचना, पूंजीवाद आदि, सभी कसौटियों में ठीक ही हैं। भाषा और तौर तरीकों का फर्क है; अन्यथा राष्ट्रहित में उनके वैश्विक फैसलों (टैरिफ़ जंग, चीन को कसना, यूरोपीय देशों के सुरक्षा खर्च का बोझ घटाना, अपने से सटे दक्षिण अमेरिकी देशों यानी पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी वर्चस्व की दादागीरी पर क्यों अमेरिका में कोई आपत्ति करेगा?

वेनेज़ुएला के तानाशाह राष्ट्रपति को उठवाने के बाद ट्रंप ने कहा है, अब से ₹पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी वर्चस्व पर फिर कभी सवाल नहीं उठेगा। अमेरिका बहुत लंबे समय से 'मुनरो डॉक्ट्रिन पर अमल के प्रति लापरवाह था। अब से ऐसा नहीं होगा।' ध्यान रहे, 'मुनरो डॉक्ट्रिन का उद्देश्य लैटिन अमेरिका से विदेशी शक्तियों को बाहर रखना है। मतलब पूंजीवादी अमेरिका को अपने पिछवाड़े या पड़ोस में सोवियत संघ, रूस, वामपंथियों का प्रभाव बर्दाश्त नहीं। इस नीति के कारण उन्नीसवीं सदी में अमेरिका ने पनामा, निकारागुआ, क्यूबा, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना आदि सभी देशों में हस्तक्षेप किया, सरकारें बदलीं, दक्षिणपंथी सरकारें बनवाईं। शीत युद्ध के दौरान क्यूबा पर तो अमेरिका और सोवियत संघ में ज़बरदस्त ठनी थी, जिसके समाधान में सोवियत संघ झुका, उसने क्यूबा से अपनी मिसाइलें हटाईं।

वे दिन वापिस लौट आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा है कि अमेरिका अब वेनेज़ुएला को 'चलाएगा', यदि ज़रूरत पड़ी तो ज़मीन पर सैनिक उतार कर भी। वेनेज़ुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उसकी कंपनियां 'बेहद विशाल संपदा' निकालेंगी। अमेरिकी और वेनेज़ुएलावासी, दोनों की अमीरी बढ़ेगी। इसके साथ ट्रंप ने कोलंबिया और क्यूबा को भी धमकाया है। उन्होंने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो पर 'कोकीन बनाकर' उसे 'अमेरिका भेजने' का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि वे अब अपने को बचाएं।

विश्व राजनीति में अपने इलाके में अपनी दबंगई की चाह हर महाबली को रही है। इसी कारण रूस के पुतिन ने यूक्रेन में पंगा बनाया। ऐसे ही चीन अपने प्रभाव क्षेत्र की ज़िद में है। हिसाब से दक्षिण एशिया में भारत का हित भी पड़ोसी देशों पर प्रभाव बनाए रखने से, बाहरी प्रभाव यानी चीन को बाहर रखे रखने में है। मगर भारत की व्यवस्था पोली है, चेहरे ठगने वाले हैं; इसलिए चीन को आंख दिखाने या अपने इलाके में अपने रुतबे की ताक़त ही नहीं है। लालबहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी (दोनों की कमान में दुनिया ने असल सैन्य क्षमता जानी थी) के अपवाद को छोड़, भारत की व्यवस्था और उसके तमाम प्रधानमंत्री या तो रक्षात्मक रहे हैं या जनता को दिखावे, शौर्य के ऑपरेशन बनाते हुए।

याद करें युगांडा के हवाईअड्डे से नागरिकों को छुड़वाने के इज़राइली ऑपरेशन को; या अमेरिका के पाकिस्तान में आतंकियों को मारने, ईरान के एटमी ठिकानों पर हमले; या वेनेज़ुएला के ताज़ा 'ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिज़ॉल्व के परिणामों को। और अब ज़रा प्रधानमंत्री मोदी के छप्पन इंची छाती की कमान में बने ऑपरेशनों पर ध्यान दे? उनके क़िस्से हैं, कहानियां हैं, फ़िल्में हैं, पर परिणाम शून्य। पिछले ग्यारह वर्षों में भारत ने उरी की छावनी में घुसपैठ देखी। वही पुलवामा की आतंकी भयावहता दहलाने वाली थी; तो पहलगाम में हत्याएं नृशंसज मगर इन घटनाओं का एक भी दोषी, आतंकी अपराधी भारत की जेल में नहीं है। जबकि ट्रंप अभी कोकीन सप्लाई के आरोप में वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति को उठवा कर न्यूयॉर्क की अदालत में पेश करने वाले हैं; उधर एटमी ख़तरे में ईरान के एटमी ठिकाने पाताल में धंसा दिए हैं। जबकि भारत की सूरमा एजेंसियों, धुरंधरों का बूता नहीं है जो वे दाऊद इब्राहिम को दबोचें या भारत में ख़ौफ़नाक घटनाओं के ज़म्मिदार आतंकी, मौलाना मसूद अज़हर, हाफ़ज़ि सईद, लख़वी, कासकर को पाकिस्तान से उठा कर जेल में डालें।

बहरहाल, अमेरिका की एजेंसियां व संस्थाएं ठोस हैं, तो नतीजे भी असल और ठोस होंगे। वेनेज़ुएला के ऑपरेशन की गूंज चीन रूस को भी हैसियत बताने वाली है। दोनों देशों के हाथ पांव फूलेंगे। वेनेज़ुएला का राष्ट्रपति रूस के भरोसे था; सो, फिर साबित है कि रूस या चीन में वह क्षमता ही नहीं कि किसी के लिए वे अमेरिका से भिड़ें। चीन आज बैटरी यानी ईवी वाहनों के उत्पादनों से वैश्विक बाज़ार में जो डंका बजाए हुए है, उस पर संकट आ सकता है। इसका अधिकांश कच्चा माल, लिथियम, निकल, कोबाल्ट, ग्रेफाइट—दक्षिण अमेरिका की खदानों से (चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया के 'लिथियम ट्रायंगल व ब्राज़ील की 'लिथियम वैली) मिलता है। सो, असंभव नहीं कि ट्रंप प्रशासन अपने रुतबे में चीन की सप्लाई रुकवाए। अमेरिकी विदेश रक्षा नीति में 'मुनरो डॉक्ट्रिन पर अमल का संकल्प ठोस हुआ, तो सर्वाधिक प्रभावित चीन होगा। दक्षिण अमेरिका को चीन ने चुपचाप लपेटे में लिया है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला, ब्रिक्स के ज़रिए चीन से जो नाता बनाए हुए हैं, वह ट्रंप प्रशासन को खटक रहा है। तभी 2026 में कोलंबिया, क्यूबा के बाद ब्राज़ील भी ट्रंप प्रशासन के निशाने में होगा। उधर ट्रंप ने ईरान के अयातुल्ला शासन को धमकी दी है कि वे अपने प्रदर्शनकारियों पर गोली न चलाएं; अन्यथा अमेरिका चूकेगा नहीं। मेरा मानना है कि इज़राइल तथा खाड़ी अरब के सुन्नी बहुल देश—सभी मिलकर—शिया ईरान पर ट्रंप प्रशासन से कार्रवाई चाहते होंगे।

ईरान भी रूस चीन पर आश्रित है; तो वेनेज़ुएला की तरह यदि ईरान का अमेरिका ने टेकओवर किया, तो विश्व राजनीति में अकल्पनीय धमाल होगा। उससे पाकिस्तान, भारत, रूस, दक्षिण एशिया—सब प्रभावित होंगे। इसलिए 2026 की शुरुआत असाधारण है। वेनेज़ुएला में अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन पर दुनिया चाहे जो कहे, हल्ला करे—पर ट्रंप रुकने वाले नहीं हैं। पिछले वर्ष उन्होंने व्यापार अर्थिकी के मोर्चे पर दुनिया को घायल किया; तो इस वर्ष वे सामरिक भूराजनीतिक मोर्चे में हैरान परेशान करने वाले हैं। नोट रखिए—कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए क्योंकि अमेरिकी व्यवस्था का कोई तोड़ नहीं है।

शाहरुख खान को गद्दार बताने वाला संगीत सोम पर बोले सपा विधायक अतुल प्रधान- ये करते हैं मीट का कारोबार

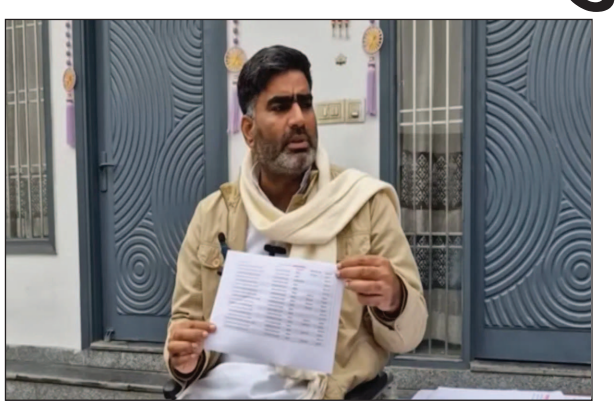

2022 से दोनों नेताओं में विवाद

सरधना के वर्तमान विधायक अतुल प्रधान एवं पूर्व विधायक संगीत सोम के बीच सियासी घमासान कोई नई बात नहीं है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में अतुल प्रधान ने संगीत सोम को पराजित किया था और सरधना सीट पर जीत हासिल की थी। उस समय से दोनों के बीच लगातार आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। एक तरफ हिंदुत्व के मुद्दे पर संगीत सोम लगातार बयान दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ अतुल प्रधान भी उन पर लगातार हमला बोल रहे हैं।

आर्यावर्त संवाददाता

मेरठ। सरधना सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान और भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम के बीच तनातनी जारी है। सपा विधायक अतुल प्रधान ने संगीत सोम पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक अतुल प्रधान ने अपने आवास पर संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संगीत सोम एक ओर तो मोइन कुरैशी के साथ मिलकर मीट का कारोबार करते हैं और फिर बॉलीवुड फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को गद्दार बताते हैं और हिंदू-मुस्लिम की सियासत करते हैं।

विधायक अतुल प्रधान ने संगीत सोम पर हमला बोलते हुए कहा कि वह मीट का कारोबार करते हैं और मुस्लिम लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं और खुद को हिंदूवादी नेता दिखाते हैं। उन्होंने संगीत सोम को दो मीट कंपनी का डायरेक्टर बताते हुए कहा कि इनकी 12-15 कंपनियों हैं या तो ये डायरेक्टर हैं या इनकी पत्नी डायरेक्टर हैं या इनकी साली डायरेक्टर हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप नए-नए हिंदू बने हैं।

इस दौरान अतुल प्रधान ने आरोपों को लेकर पत्रकारों को दस्तावेज भी दिखाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि संगीत सोम की मीट फैक्ट्रियों से विदेशों में मीट की सप्लाई की जाती है। इसके अतिरिक्त वह शराब का कारोबार से भी गलत तरीके से करते हैं।

अतुल प्रधान की सीबीआई जांच की मांग

अतुल प्रधान ने सरकार से कहा कि इसके पहले संगीत सोम पर हमला हुआ था और गोलियां चलाई गई थी, लेकिन उस मामले का अभी तक पर्दा नहीं खुला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से पिछले 11 सालों में सोम की सुरक्षा पर 66 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उन्हें केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने मांग की कि उनकी सुरक्षा की समीक्षा होनी थी, क्योंकि उन्हें बांग्लादेश से धमकी मिली है, लेकिन यह सुरक्षा बचाने के लिए एक प्रोपगेंडा हैं। यह मामले खुलने चाहिए और उनकी सीबीआई जांच हो। वे सुरक्षा का इस्तेमाल करके जमीनों और गरीब लोगो के मकानों पर कब्जा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि इनकी संपत्ति की सरकार जांच करे।

बांग्लादेश से सोम को मिली थी धमकी

बता दें कि हाल में संगीत सोम को बांग्लादेश से जुड़े नंबर से धमकी मिली थी और उन्हें बम से उड़ाने की बात कही गयी थी। शाहरुख खान की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स में बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को शामिल करने के विवाद के बाद यह मामला सामने आया था। संगीत सोम ने शाहरुख खान को गद्दार बताया था, जिससे राजनीतिक विवाद पैदा हो गया था।

अतुल प्रधान ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में जिस तरह से मर्डर हो रहे हैं। इस पर सरकार संज्ञान ले। देश की सरकार एक ओर शाहरुख खान को अवॉर्ड देती है, वहीं उनका एक नेता शाहरुख खान के नाम पर हिंदू-मुस्लिम की सियासत करता है। उन्होंने मांग की कि बीसीसीआई को तत्काल बांग्लादेश से अपने संबंध खत्म कर देने चाहिए।

हमले के खिलाफ एसयूसीआई का विरोध प्रदर्शन

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। साम्राज्यवादी अमेरिका द्वारा वेनेजुएलापर बर्बरहमला करने और उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो एवं उनकी पत्नी का अपहरण कियेजाने के खिलाफ एसयूसीआई की जिला कमेटी की तरफ से गुरुवार को बदलापुर चौक पर विरोध प्रदर्शन किया।इसके पूर्व कार्यकर्ताओं ने सब्जी मण्डी स्थित पार्टी कार्यालय से जुलूसनिकाल कर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी किया। पार्टी के जिला सचिव कॉमरेड अशोककुमार अमेरिका के बेहद घृणित सैन्यहमले की घोरनिंदा करते हुए कहा कि सम्बोधन में कहा कि यह हमला केवल वेनेजुएला पर ही नहीं, बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका पर किया गया है। जिसका उद्देश्य वहां स्थित सभी देशों को बंदूक की नोक पर अधीन करना है। अमेरिका झूठा आरोप लगा कर वेनेजुएला पर हमला किया है।जबकि उसकीमंशा तेल व खनिज पदार्थों को हथिया, अपनी पिट्ठू सरकार बनाना है। ट्रंप अपने आप को शांति का दूत कहते हैं। लेकिन ये दुनिया में अशांति फैला रहे हैं और दादागिरी कर रहे हैं । कॉमरेड प्रमोदकुमार शुक्ल,राजेंद्र प्रसाद तिवारी, दिलीप कुमार ने सम्बोधित किया। इस अवसर पर इन्दुकुमार शुक्ल,राजबहादुर विश्कर्मा,दिनेश कान्त मौर्य रामप्यारे, विजय प्रकाश गुप्त,लालता प्रसाद मौर्य, मिथिलेश कुमार मौर्य,राकेश निषाद,संतोष कुमार,उमा शंकर, आदि मौजूद रहे।

कॉल करके बाल विवाह की दें जानकारी

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर ओर कॉल करने पर आप को तत्काल सहायता मिलेगी। आप नही चाहेंगे तब तक आपको न ही बुलाया जाएगा और न ही आपका नाम सार्वजनिक होगा। यह बातें गुरुवार को जफराबाद थाने के प्रांगण में बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत आयोजित जागरूकता अभियान में बोलते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी विजय कुमार पांडेय ने कही। श्री पाण्डेय ने कहा कि बाल विवाह में करवाने में माँ बाप तो दोषी है ही उसके साथ ही शादी करवाने के कार्यक्रम में शामिल पंडित,नाउ, टेंट हाउस,मैरेज लान वाला,डीजे वाला,गलत जन्मप्रमाण पत्र गलत जारी करने वाला समान रूप से कानूनन दोषी माने जाएंगे।लड़का लड़की में समाज को विभेद करना रोकना होगा।जिला बाल सरंक्षण अधिकारी चंदन राय ने कहा कि हम सभी को मिलकर समाज मे व्याप्त बाल विवाह मुक्त भारत बनाने

में लग जाय। हमे जनपद को इस बुराई से मुक्त करवाना होगा।इसके लिए हमे पूरी इच्छा शक्ति से लगना होगा।उन्होंने कहा कि आने वाले समय मे ग्रामीणों को नेतृत्व करने वाले प्रधान,सभासद,चेयरमैन जैसे जिम्मेदार लोगों को भी इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिम्मेदार बनाने के लिए शासन में प्रस्ताव बन रहा है। थानाध्यक्ष श्रीप्रकाश शुक्ल,एसएसआई अरविंद सिंह ने भी लोगों को बाल विवाह से होने वाले नुकसान की जानकारी दिया। अंत मे श्री पाण्डेय ने मौजूद लोगों को हाथ उठवाकर शपथ दिलाया कि हम लोग बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण करूंगा।इसके बाद हस्ताक्षर कराया गया। शीतला प्रसाद गिरी,लालबहादुर यादव,चौकी प्रभारी राधेश्याम सिंह,तेजबहादुर सिंह,पंकज पूरी,जयशंकर यादव आदि मौजूद रहे।

साली ने किया जीजा को जलाकर मारने का प्रयास

जौनपुर। नगर के सिपाह मोहल्ले में एक महिला ने अपने जीजा को आग लगाकर जान से मारने का प्रयास किया। इस दौरान उसने अपनी बहन को भी पीटकर बेहोश कर दिया। गंभीर रूप से झुलसे जीजा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। पीड़ति की पहचान बलिया निवासी 30 वर्षीय संदीप मिश्रा पुत्र संतोष मिश्रा के रूप में हुई है। उनकी पत्नी प्रतिमा चौहान मड़ियाहूं गांव की रहने वाली हैं। संदीप और प्रतिमा 1 जनवरी से सिपाह मोहल्ले में किराए के मकान में रह रहे थे। वे कोर्ट मैरिज के लिए जौनपुर आए थे। आरोपी साली का नाम निशा है। यह घटना गुरुवार को दोपहर करीब 12 बजे हुई। आरोप है कि निशा ने पहले अपनी बहन प्रतिमा को डंडे से पीटकर बेहोश कर दिया। इसके बाद उसने अपने जीजा संदीप पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी, जिससे वह बुरी तरह झुलस गए। घटना की सूचना मिलते ही 112 पुलिस मौके पर पहुंची।

5 साल का अफेयर, शादी के बाद पत्नी को पढ़ाया, जब बन गई दारोगा तो... हापुड़ के इस केस में कौन सही?

आर्यावर्त संवाददाता

हापुड़। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पत्नी को पढ़ा लिखाकर दरोगा बनाने वाले पति गुलशन पर दहेज मांगने और उत्पीड़न करने की FIR दर्ज हुई है। इसे लेकर पति गुलशन ने हापुड के एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह से सही जांच करने की गुहार लगाई है। 13 नवंबर 2025 को दरोगा पत्नी पायल रानी ने अपने पति गुलशन और उसके परिवार के छह सदस्यों के खिलाफ हापुड़ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है।

दरअसल, हापुड़ के मोहल्ला गणेशपुरा निवासी और जनपद बरेली में तैनात महिला सब इंस्पेक्टर पायल रानी ने 13 नवंबर 2025 को पुलिस अधीक्षक हापुड़ को शिकायत देकर हापुड नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया है। पायल रानी का आरोप है कि उनकी शादी 2 दिसंबर 2022 को पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के गांव पूठा हुसैनपुर निवासी गुलशन के साथ हुई थी। शादी के समय मायके वालों ने

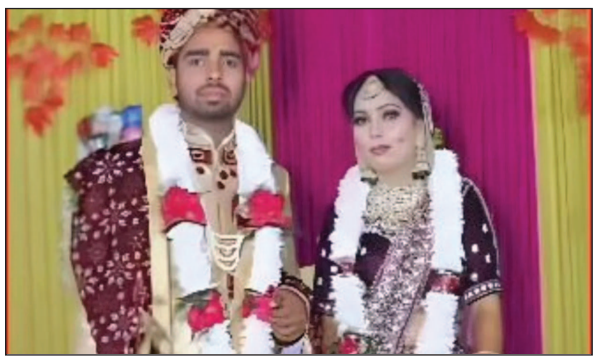

भरपूर दहेज दिया, लेकिन ससुराल वाले संतुष्ट नहीं हुए।

आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही पति गुलशन, सास-ससुर और अन्य रिश्तेदारों ने अतिरिक्त दहेज की मांग शुरू कर दी। पायल रानी ने अपनी शिकायत में बताया कि ससुराल वाले उनसे 10 लाख रुपये नकद और एक कार की मांग कर रहे थे। जब यह मांग पूरी नहीं हुई, तो उत्पीड़न बढ़ गया। आरोप है कि ससुराल वालों ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, बेरहमी से पीटा और यहां तक कि तेजाब फेंककर जान से मारने की धमकी भी दी। ये धमकियां इतनी गंभीर थीं कि पायल रानी को अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा।

पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह के आदेश पर सदर कोतवाली पुलिस ने पायल रानी की तहरीर पर पति गुलशन सहित छह ससुरालजनों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट, धमकी और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया।

'पत्नी को पढ़ाया-लिखाया मैंने'

जबकि, वहीं पति गुलशन का कहना है- मैं और पायल साल 2016 से अफेयर में हैं। हम दोनों साथ पढ़ते थे। हम दोनों ने वर्ष 2021 में कोर्ट मैरिज कर ली थी, जिसके बाद अपने परिजनों को समझाकर हमारी बिना दान दहेज के हिंदू रीति-रिवाज के साल 2022 में शादी हो गई। पायल मेरे साथ घर में रहने लगी। मैंने अपनी पत्नी पायल रानी को पढ़ा-लिखाकर सब-इंस्पेक्टर बनवाया है। अपनी मेहनत से कमाए रुपयों से उन्हें पढ़ाया और समर्थन किया, जिससे उन्हें नौकरी मिली। लेकिन अब पायल रानी ने उन पर और परिवार पर झूठा मुकदमा लिखवा दिया है। गुलशन ने हापुड़ के एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह से मुलाकात कर सही और निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई है। और पूरी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी।

अस्पताल में लापरवाही से पशु पालकों में आक्रोश

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। बदलापुर क्षेत्र के घनश्यामपुर बाजार स्थित सरकारी पशु अस्पताल में तैनात चिकित्सकों की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। गलत जांच और उपचार के चलते एक गर्भवती गाय ने सात महीने के मृत बछड़े को जन्म दे दिया। घटना के बाद पशुपालकों में गहरा आक्रोश है और सरकारी पशु चिकित्सा सेवाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं।कुशहा द्वितीय गांव निवासी सुभाष गुप्ता उर्फ भोला तीन दिन पहले अपनी गाय का गर्भ परीक्षण कराने घनश्यामपुर स्थित पशु अस्पताल पहुंचे थे। आरोप है कि वहां मौजूद चिकित्सक ने बिना समुचित जांच के गाय के गर्भवती होने से इनकार कर दिया। डॉक्टर ने यह कहते हुए इलाज शुरू कर दिया कि गाय की बच्चेदानी में गांठ है, जबकि वास्तविक स्थिति इसके विपरीत थी।पीड़ति का कहना है कि लगातार तीन दिनों तक गलत उपचार चलता रहा। गुरुवार को हालात उस समय बिगड़ गए, जब गाय ने लगभग सात महीने के मृत बछड़े को जन्म दिया। इस घटना से पशुपालक और उसके परिवार में कोहराम मच गया। गाय की हालत भी चिंताजनक बनी हुई है। घटना से पशुपालक और उसके परिवार में कोहराम मच गया। गाय की हालत भी चिंताजनक बनी हुई है।घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में पशु अस्पताल के पास जुट गए और लापरवाह चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते सही जांच और इलाज होता, तो गर्भस्थ बछड़े की जान बचाई जा सकती थी।

अलीगढ़ में ये कैसा परिवार नियोजन? नसबंदी कराने के बावजूद गर्भवती हो गईं 64 महिलाएं

आर्यावर्त संवाददाता

अलीगढ़। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिले में परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत 2025 में नसबंदी कराने के बावजूद 64 महिलाएं दोबारा गर्भवती हो गईं। इन मामलों में विभाग ने मुआवजे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि नियमों की अनदेखी के कारण 5 महिलाओं के दावे निरस्त भी कर दिए गए हैं।

सीएमओ डॉ। नीरज त्यागी के अनुसार नसबंदी के बाद गर्भवती हुई महिलाओं द्वारा अपील किए जाने पर अब तक 62 केस में मुआवजे की राशि विभाग के पास आ गई है। वहीं 6 ब्लॉकों से करीब 5 दावों को निरस्त कर दिया गया है। नियम अनुसार गर्भधारण की सूचना 90 दिनों के भीतर विभाग को देनी अनिवार्य है।

उन्होंने कहा कि खारिज किए गए दावों में लोधा और छर्रा के दो-दो कैसे हैं, जबकि अकराबाद, जवां, टप्पल व गोंडा का एक-एक केस शामिल है।

कब कितनी हुई थी नसबंदी

जिले में परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत 2024 में 6,240 महिला व पुरुषों ने नसबंदी कराई थी। वहीं 2025 में 3,042 महिला-पुरुषों ने नसबंदी कराई। जिनमें महिलाओं का आंकड़ा 99% नसबंदी का रहा।

पहले भी आए हैं इस तहर के मामले

2024 में जिले के सरकारी अस्पताल में कराई गई नसबंदी के फेल होने के कई मामले सामने आए थे। पिछले 4 वर्षों में करीब 81 महिलाओं की नसबंदी फेल हो चुकी है। नसबंदी करने के बाद भी महिलाएं गर्भधारण कर रही हैं। जिससे सरकारी सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। यह खुलासा परिवार नियोजन की इन्डेमिनिटी योजना के तहत जारी की गई रिपोर्ट से हुआ था।।

कितनी महिलाओं की हो चुकी है नसबंदी?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिले में अब तक करीब 6000 महिलाओं की नसबंदी की जा चुकी है। नसबंदी के बाद प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। सीएमओ डॉ नीरज त्यागी ने बताया कि नसबंदी के बाद अगर कोई महिला गर्भवती होती है तो उसे 60 हजार रुपए मिलते हैं। जिसमें 30 हजार रुपए राज्य व 30 हजार रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिए जाते हैं।

सर्वेश्वरी समूह ने 50 गरीबों को कंबल ओढ़ाया

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। श्री सर्वेश्वरी समूह शाखा बदलापुर द्वारा गुरुवार को दुगौली खुर्द में जरूरत मंद लोगों को कंबल वितरित किया गया। कल अघोरान्ना परो मंत्रः का अखंड कीर्तन शुभारंभ होकर संपन्न हुआ।कीर्तन की पूर्णाहुति के बाद कुल पचास जरूरत मंद लोगों को कम्बल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कम्बल वितरण कार्यक्रम में श्री कृष्णकांत सिंह प्रधानाध्यापक, सीबी सिंह, रामजीत यादव, कृपाशंकर सिंह सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। प्रतापगढ़ से आए श्री सर्वेश्वरी समूह के सदस्य अंजनीकुमार सिंह सपरिवार इस पुनीत कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के आयोजक शाखा मंत्री दल सिंगार सिंह फौजी ने सभी लोगों को सम्समान आवभगत और प्रसाद वितरण के साथ लोगों के प्रति आभार जताया।

यूपी एसआईआर में 2.89 करोड़ कटने से क्या टेंशन में भाजपा, नेताओं को वोट जुड़वाने और कटवाने का दिया गया टारगेट

आर्यावर्त संवाददाता

अयोध्या। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग की ओर से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के बाद जारी की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। ड्राफ्ट लिस्ट में 6 जनवरी को जारी की गई लिस्ट में करीब 2।89 करोड़ वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं, इस तरह से अब कुल वोटर्स की संख्या 15।44 करोड़ से घटकर 12।55 करोड़ रह गई। विपक्षी दल एक ओर इसे 'लोकतंत्र की हत्या' और 'साजिश' बता रहे हैं, तो वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए यह ज्यादा सिरदर्द बन गया है क्योंकि पार्टी नेताओं का मानना है कि हटाए गए नामों में उनके कोर वोटर ज्यादा है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मंगलवार (6 जनवरी) को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया

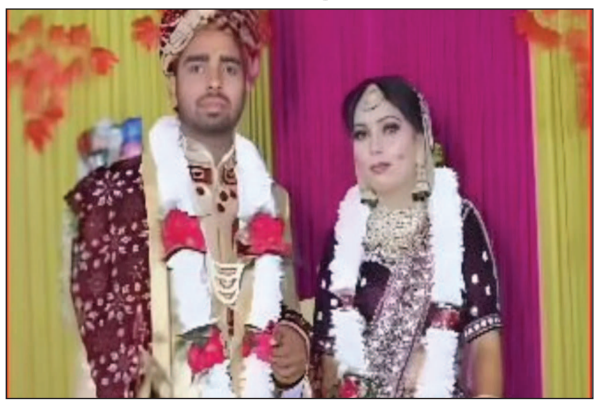

कि SIR के तहत बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) ने घर-घर सर्वे किया। इस दौरान 46।23 लाख मृत वोटर्स, 2।17 करोड़ वोटर्स स्थायी रूप से माइग्रेट हुए तो 25।47 लाख डुप्लीकेट वोटर्स पाए गए। ड्राफ्ट में 81।30% नाम बरकरार रखे गए, लेकिन इसमें से 18।70% वोटर्स की कटौती ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है।

BJP के खेमे में क्यों सबसे अधिक चिंता?

बीजेपी को डर है कि नाम कटने से 2027 के विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत और सीटों पर असर पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिसंबर में ही कार्यकर्ताओं से कहा था कि "हटाए जा रहे वोटरों में 85-90% हमारे वोटर्स हैं।" पार्टी अब राज्य के 1।62 लाख बूथों पर फॉर्म-6 बांट रही है। कार्यकर्ता घर-घर जाकर नए मतदाताओं, खासकर 18 साल पूरे कर चुके युवाओं, शादी के बाद पता बदलने वाली महिलाओं और नए बसे लोगों को जोड़ने में जुटे हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद सीएम योगी ने मंगलवार शाम को ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी से जुड़े सभी पदाधिकारियों की अहम बैठक बुलाई। बैठक में प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक संगठन के लोग और सांसद तथा विधायक शामिल हुए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने सभी सांसद और विधायकों को निर्देश दिया कि पहली लिस्ट में जिन भी वैध लोगों के वोट कट गए हैं उनको फिर से जुड़वाना है।

MP-MLA के साथ मंत्रियों को भी टारगेट

सीएम योगी ने साफ-साफ कह दिया कि सभी सांसद और विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में बूथ स्तर तक जाकर इस प्रक्रिया में जुट जाएं और अभियान चलाकर उन लोगों के नाम लिस्ट में शामिल कराएं जो छूट गए हैं। साथ ही उन्होंने अपने सभी मंत्रियों को भी अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर जमीन पर उतरने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। अपात्र वोटर्स को लेकर मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों को कहा कि ड्राफ्ट सूची के आने के बाद अपने प्रभार जिलों की वोटर लिस्ट हासिल करिए और विधानसभा वार जांच करवाएं। किसी भी पात्र वोटर्स का नाम छूटना नहीं चाहिए। फॉर्म भरवाकर नाम जुड़वाया जाए और अपात्र या डुप्लीकेट नामों पर आपत्ति दर्ज कराकर हटवाया भी जाए। सीएम योगी ने का कहना है कि इस मेहनत से लोकतंत्र मजबूत होगा और चुनावी रास्ते सुगम होंगे। दावे-आपत्तियां 6 जनवरी से 6 फरवरी तक दर्ज कराई जा सकती हैं। जबकि फाइनल लिस्ट 6 मार्च को आएगी। बैठक में शामिल हुए कर्नलगंज विधानसभा के विधायक अजय सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सभी को निर्देश दिए हैं कि छूटे हुए वोटर्स के नाम जुड़वाए जाएं और जो गलत नाम जुड़ गए हैं उन पर आपत्ति दर्ज कराकर हटाए जाएं।

यह बीजेपी की साजिश: अजय राय

गोंडा जिले के तरबगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रेम नारायण पांडे ने कहा, "एक बार आप सब लोग अभियान चलाकर बूथ स्तर तक निगरानी करके जो नाम छूट गए हैं या मिस हो गए हैं, उनको जुड़वाने की कोशिश करिए। साथ ही अगर आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में गलत नाम जुड़ गए हैं तो भी आपत्ति करिए क्योंकि अभी भी मौका है और इसमें सुधार हो जाएगा, जिससे विधानसभा चुनाव आसान होगा।

पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ल ने कहा, "यह अभियान पारदर्शिता और लोकतंत्र की मजबूती के लिए है। हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता दिन-रात मेहनत कर रहे हैं ताकि कोई पात्र मतदाता वंचित न रहे।" हालांकि, अंदरखाने बीजेपी के कर्ताधर्ता मान रहे हैं कि शहरी और कुर्मी-ओबीसी वोटरों के नाम ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जो पार्टी का कोर बेस हैं।

वोटर लिस्ट में नाम कैसे जुड़वाएं?

दूसरी ओर, बीजेपी के उलट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसे साजिश' करार दिया। समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा समेत कई अन्य ने कहा कि लाखों असली वोटर्स के नाम काटे गए, जबकि उनके पास सभी दस्तावेज हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इसे 'बड़ी साजिश' बताया और जांच की मांग की। सपा का दावा है कि इससे बीजेपी को ही नुकसान होगा, क्योंकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उनके वोटर ज्यादा प्रभावित हुए हैं। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने या फिर कटवाने के लिए 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक दावा और आपत्ति बताने का समय दिया है। पात्र व्यक्ति फॉर्म-6 भरकर अपना नाम शामिल करवा सकते हैं।

पत्ता गोभी के कीड़ों को ऐसे करें खत्म, ताकि न हों किसी बीमारी के शिकार

सर्दी के मौसम में बाजार में काफी हरी सब्जियां मिलने लगती हैं। इन्हीं में शामिल है पत्ता गोभी.... पत्ता गोभी एक ऐसी सब्जी है, जो लगभग हर घर में इस्तेमाल की जाती है। इसकी मदद से घरों में सलाद, सब्जी, मंचूरियन और कई तरह की डिशेज बनाई जाती हैं। पर, क्या आप जानते हैं कि गोभी की परतों में छोटे-छोटे कीड़े छिपे हो सकते हैं। अगर इसे ठीक से साफ न किया जाए, तो ये कीड़े शरीर में जाकर गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। कई मामलों में तो इन कीड़ों की वजह से लोगों की मौत तक हो गई है। इसलिए पत्ता गोभी को काटकर या पकाने से पहले अच्छी तरह साफ करना बेहद जरूरी है। गोभी को सिर्फ ऊपर से धो लेना काफी नहीं होता, क्योंकि कीड़े पत्तों की अंदरूनी परतों में छिपे रहते हैं। इस लेख में हम आपको पत्ता गोभी को सही तरीके से साफ करने का आसान और असरदार तरीका बताएंगे, जिससे आपकी सेहत सुरक्षित रहे और खाने का स्वाद भी बना रहे।

ये है सही तरीका

अगर आप पत्ता गोभी को सही से साफ करना चाहते हैं तो इसे साफ करने की शुरुआत हमेशा उसकी बाहरी पत्तियों से करनी चाहिए। सबसे पहले पत्ता गोभी की ऊपर की 2 से 3 पत्तियां निकालकर अलग कर दें और फेंक दें, क्योंकि इन्हीं पत्तियों पर सबसे ज्यादा धूल, मिट्टी, कीटनाशक और छोटे कीड़े चिपके होते हैं। इसके बाद पत्ता गोभी को साफ चाकू की मदद से बीच से दो या चार हिस्सों में काट लें। ऐसा करने से अंदर की परतें खुल जाती हैं और छिपे हुए कीड़े आसानी से नजर आने लगते हैं।

अब एक बड़े और गहरे बर्तन में साफ पानी भरें। इसमें एक से दो चम्मच नमक या फिर थोड़ा सा सिरका मिला दें। इस नमक या सिरके वाले पानी में पत्ता गोभी के कटे हुए टुकड़ों को पूरी तरह डुबोकर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। इस दौरान नमक या सिरका का असर अंदर छिपे कीड़ों और बैक्टीरिया पर पड़ता है, जिससे वे पत्तियों से बाहर निकल आते हैं और पानी में तैरने लगते हैं।

समय पूरा होने के बाद पत्ता गोभी को पानी से निकालें और साफ बहते पानी में 2 से 3 बार अच्छी तरह धोएं। ध्यान रखें कि हर पत्ती को थोड़ा खोलकर धोया जाए, ताकि कोई गंदगी या कीड़ा अंदर न रह जाए। अंत में पत्ता गोभी को छलनी या टोकरी में रखकर अतिरिक्त पानी निकलने दें। पूरी तरह पानी सूख जाने के बाद पत्ता गोभी पकाने या सलाद बनाने के लिए पूरी तरह सुरक्षित हो जाती है।

आंखों और माथे में रहता है दर्द? जानें ये किस बीमारी की वजह से है

आंखों और माथे में दर्द की समस्या कई लोगों को अक्सर परेशान करती है। अधिकतर लोग इसे सामान्य थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह शरीर में छिपी कुछ बीमारियों का संकेत भी हो सकता है।

आजकल बदलती लाइफस्टाइल, बढ़ता स्क्रीन टाइम और तनाव की वजह से कई लोगों को आंखों और माथे में दर्द की शिकायत रहने लगी है। यह दर्द कभी हल्का होता है तो कभी इतना तेज कि रोज़मर्रा का काम भी मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों को सुबह उठते ही दर्द महसूस होता है, तो कुछ को देर तक मोबाइल या लैपटॉप देखने के बाद। कई बार लोग इसे सामान्य थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन लगातार बना रहने वाला दर्द किसी अंदरूनी समस्या का संकेत भी हो सकता है। आंखों और माथे में होने वाला दर्द अलग-अलग बीमारियों से जुड़ा हो सकता है, जिसे समय पर पहचानना जरूरी है। आइए इस बारे में जानते हैं।

आंखों और माथे में दर्द रहना किस बीमारी का संकेत हैं?

आरएमएल हॉस्पिटल में मेडिसिन विभाग में डायरेक्टर प्रोफेसर डॉ। सुभाष गिरि बताते हैं कि आंखों और माथे में दर्द का सबसे आम कारण साइनस की समस्या हो सकती है। साइनस में सूजन या इंफेक्शन होने पर माथे, नाक की जड़ और आंखों के आसपास भारीपन और दबाव जैसा दर्द महसूस होता है। माइग्रेन भी इसकी एक बड़ी वजह है, जिसमें सिर के एक हिस्से के साथ आंखों में तेज दर्द, मतली, उल्टी और तेज रोशनी से परेशानी हो सकती है।

इसके अलावा आंखों की कमजोरी, चश्मे का गलत नंबर या लंबे समय तक स्क्रीन देखने से होने वाला आई स्ट्रेन भी इस दर्द को बढ़ा देता है। कुछ मामलों में हाई ब्लड प्रेशर, डिहाइड्रेशन और ज्यादा तनाव के कारण भी आंखों और माथे में लगातार दर्द बना रह सकता है। नींद की कमी होने पर आंखों में जलन, भारीपन और सिरदर्द के साथ यह समस्या और गंभीर हो सकती है।

आंखों और माथे में दर्द कब ज्यादा होता है? किसके लिए खतरनाक?

यह दर्द अक्सर ज्यादा देर तक मोबाइल, लैपटॉप या टीवी देखने के बाद बढ़ जाता है। सुबह के समय साइनस के मरीजों को ज्यादा दर्द महसूस हो सकता है। तनाव, नींद पूरी न होना और तेज धूप में निकलना भी दर्द को बढ़ा सकता है। बच्चों, बुजुर्गों और पहले से माइग्रेन या आंखों की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए यह ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर दर्द के साथ धुंधला दिखना, उल्टी, तेज बुखार या आंखों में सूजन हो, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

कैसे करें बचाव

रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, ताकि शरीर में डिहाइड्रेशन न हो।

स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल करने से बचें और बीच-बीच में आंखों को आराम दें।

सही नंबर का चश्मा लगाएं और समय-समय पर आंखों की जांच कराएं।

ठंड, धूल और प्रदूषण से बचाव करें, साइनस की समस्या हो तो विशेष सावधानी रखें।

पूरी नींद लें और तनाव कम करने के लिए योग या मेडिटेशन अपनाएं।

बेबी पालक है पोषक तत्वों का भंडार, इससे बनाकर खाएं ये 5 अनोखे पकवान

पालक तो सभी के घरों में बनती है, लेकिन इसकी एक खास किस्म के बारे में काफी कम लोग जानते हैं। हम बात कर रहे हैं बेबी पालक की, जिसे छोटी पालक नाम से भी जाना जाता है। यह आम पालक की तुलना में कम कड़वी होती है और इसे कच्चा भी खाया जा सकता है। यह विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और प्रोटीन का भंडार होती है। आप बेबी पालक से ये व्यंजन बना सकते हैं, जिनकी रेसिपी आसान है।

बेबी पालक का लजानिया

सबसे पहले पैन में तेल गर्म करें और लहसुन, प्याज, नमक, काली मिर्च और बेबी पालक को भून लें। इस मिश्रण को निचोड़कर इसका पानी निकाल दें और अलग रख दें। मिक्सी में रिकोटा चीज, परमजान चीज, जायफल, क्रीम, नमक, काली मिर्च और ओरिगैनो पीस लें। इसमें बेबी पालक वाला मिश्रण डालकर दोबारा पीसें। मक्खन, मैदा, दूध और चीज मिलाकर वाइट सॉस तैयार करें। बेकिंग ट्रे पर लजानिया शीट, दोनों सॉस और चीज की लेयर लगाते जाएं और बेक करें।

ग्रीन स्मूदी

अगर आप बेबी पालक से कुछ पीने के लिए बनाना चाहते हैं तो ग्रीन स्मूदी सही रहेगी। इसके लिए सबसे पहले एक ब्लेंडर में बेबी पालक को पीस लें। इसके बाद इसमें बादाम का दूध, एक केला, आधा कप जमे हुए फल और एक चम्मच सब्जा के बीज डालकर दोबारा पीस लें। इसे गिलास में निकालें और सुबह नाश्ते के वक्त सेवन करें। यह स्मूदी फाइबर से समृद्ध होगी और आपके शरीर को ताकत से भर देगी।

बेबी पालक और स्ट्रॉबेरी का सलाद

बेबी पालक से बनने वाला स्ट्रॉबेरी सलाद बेहद स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले प्याज, चेरी टमाटर और खीरे को टुकड़ों में काट लें। ड्रेसिंग बनाने के लिए एक कटोरे में सिरका, जैतून का तेल, खसखस, शहद, सरसों, नमक और काली मिर्च मिलाएं। एक बड़े कटोरे में सभी सब्जियां, बेबी पालक और कटी हुई स्ट्रॉबेरी मिलाएं। अब ऊपर से ड्रेसिंग छिड़कें और आनंद लेकर खाएं।

बेबी पालक वाला पेस्तो पास्ता

पास्ता के शौकीन हैं तो एक बार बेबी पालक वाला पेस्तो पास्ता बनाएं। इसके लिए कटोरे में पानी गर्म करें और उसमें तेल और नमक डालकर पास्ता उबाल लें। इसे छानकर अलग रखें और एक कटोरी में पास्ता का पानी बचा लें। सॉस बनाने के लिए बेबी पालक, बेजिल, लहसुन, चिलगोजे के बीज, जैतून का तेल, चीज और नमक पीसें। एक पैन में सॉस को पकाएं, उसमें पास्ता और उसका बचा हुआ पानी शामिल करें और चीज डालकर खाएं।

बेबी पालक का सूप

सर्दियों में सूप पीना दिल को खुश कर देता है। इस मौसम में आप बेबी पालक का पौष्टिक सूप बना सकते हैं, जो गर्माहट के साथ-साथ पोषण भी देगा। इसके लिए पैन में जैतून का तेल गर्म करें और उसमें लहुसन और प्याज भूनें। इसमें आलू डालकर पकाएं और सब्जियों का शोरबा शामिल करें। इसके बाद इसमें बेबी पालक डालें और अच्छी तरह पकने दें। सूप को ब्लेंड करें और नमक, काली मिर्च और क्रीम मिलाकर पिएं।

कम पैसे में विदेश ट्रिप का मजा लें, जानें कौन से देश हैं भारत से भी सस्ते

अक्सर लोगों को लगता है कि विदेश यात्रा करना बहुत महंगा होता है और इसके लिए भारी बजट की जरूरत होती है। लेकिन सच ये है कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं, जहां घूमना भारत के कई बड़े शहरों से भी सस्ता पड़ सकता है। कम बजट में शानदार होटल, सस्ता खाना, लोकल ट्रांसपोर्ट और खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट्स इन देशों को भारतीय यात्रियों के लिए परफेक्ट बनाते हैं।

अगर आप इस साल विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन बजट की वजह से हिचकिचा रहे हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सही डेस्टिनेशन चुनकर आप कम खर्च में यादगार इंटरनेशनल ट्रिप का मजा ले सकते हैं। खास बात ये है कि इन देशों में भारतीयों को वीजा भी आसानी से मिल जाता है या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा उपलब्ध है। कई देशों में तो वीजा की जरूरत भी नहीं है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ सस्ते विदेशी देश, जहां आप इस साल घूम सकते हैं।

नेपाल

नेपाल भारत के सबसे सस्ते विदेशी ट्रैवल डेस्टिनेशन में शामिल है। यहां खाना, होटल और ट्रांसपोर्ट काफी किफायती है। भारतीय मुद्रा यहां आसानी से चल जाती है। यहां का खाना भारतीयों को बेहद पसंद आता है। खास बात तो ये है कि यहां जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।

श्रीलंका

श्रीलंका में खूबसूरत बीच, पहाड़ और संस्कृति देखने को मिलती है। खासतौर पर ये देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए फेमस है। यहां का खाना और लोकल ट्रांसपोर्ट बजट फ्रेंडली है। भारतीय नागरिकों को श्रीलंका जाने के लिए वीजा की आवश्यकता होती है, जिसे यात्रा से पहले ऑनलाइन आवेदन करके प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी।

वियतनाम

वियतनाम कम बजट में विदेश घूमने के लिए शानदार विकल्प है। यहां होटल, स्ट्रीट फूड और घूमने की जगहें बेहद सस्ती हैं। यहां आसानी से 2 से 3 हजार रुपये खर्च करके आप प्रतिदिन घूम सकते हैं। होटल में कमरे बेहद आसानी से एक से 2 हजार में मिल जाएंगे। यहां आपको पहुंचने के बाद वीजा मिल जाएगा।

इंडोनेशिया

बाली जैसे खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस के बावजूद इंडोनेशिया भारत से ज्यादा महंगा नहीं है। सही प्लानिंग से कम खर्च में ट्रिप हो सकती है। भारत में कई ट्रेवल एजेंट्स बाली का पूरा ट्रिप बजट में प्लान करते हैं। यहां भी आपको वीज़ा-ऑन-अराइवल की सुविधा मिलती है, जिस वजह से आपका काफी समय बच जाता है।

थाईलैंड

थाईलैंड भारतीय पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। यहां का स्ट्रीट फूड, होटल और ट्रांसपोर्ट जेब पर भारी नहीं पड़ता। खासतौर पर अगर आपको नाइट लाइफ पसंद है तब तो थाईलैंड जाना बनता है। यहां वीजा लेने के नियमों में कुछ बदलाव हुए हैं, जिनके बारे में पता करने के बाद ही आप वहां जाएं।

क्या लो एनएवी वाले म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना ज्यादा फायदेमंद है? दूर कर लीजिए कंफ्यूजन

अक्सर नए निवेशकों के मन में यह सवाल आता है कि क्या कम NAV (नेट एसेट वैल्यू) वाले म्यूचुअल फंड में निवेश करना ज्यादा फायदेमंद होता है? कई लोग शेयर बाजार की तरह यह मान लेते हैं कि कम कीमत वाला फंड सस्ता है और भविष्य में ज्यादा रिटर्न देगा। लेकिन म्यूचुअल फंड के मामले में NAV को समझना और उससे जुड़े भ्रम को दूर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ कम NAV देखकर निवेश का फैसला लेना सही रणनीति नहीं मानी जाती।

क्या होती है NAV?

NAV का मतलब होता है किसी म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की मौजूदा कीमत। यह कीमत फंड की कुल संपत्ति से उसकी देनदारियां घटाकर निकाली जाती है। जब कोई नया म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है, तो उसका NAV जितना होगा, उसमें समय के साथ फंड का अच्छा प्रदर्शन करने पर बढ़ोतरी होती है।

इसलिए कम NAV का मतलब यह नहीं है कि फंड सस्ता है, बल्कि यह सिर्फ यह दिखाता है कि फंड अभी शुरुआती चरण में हो सकता है।

निवेश से मिलने वाला फायदा किस बात पर निर्भर?

असल में निवेश से मिलने वाला फायदा इस बात पर निर्भर करता है कि फंड का पोर्टफोलियो कैसा है, फंड मैनेजर का अनुभव कितना है और फंड की निवेश रणनीति कितनी मजबूत है। उदाहरण के लिए, यदि आपने ₹10 NAV वाले फंड में ₹10,000 लगाए और NAV दोगुना होकर ₹20 हो गया, तो आपको वही रिटर्न मिलेगा जो ₹100 NAV वाले फंड में निवेश करने पर NAV के ₹200 होने से मिलता। इन दोनों मामलों में प्रतिशत रिटर्न समान ही है।

इन फैक्टर्स पर जरूर करें गौर

लो NAV वाले फंड का एक मनोवैज्ञानिक फायदा जरूर होता है कि निवेशक ज्यादा यूनिट्स खरीद पाता है, जिससे उसे संतोष महसूस होता है। लेकिन ज्यादा यूनिट्स का मतलब ज्यादा मुनाफा नहीं होता। अगर फंड का प्रदर्शन कमजोर है, तो कम NAV होने के बावजूद रिटर्न कम ही रहेगा। इसलिए निवेश से पहले फंड का ट्रैक रिकॉर्ड, एक्सपेंस रेशियो, जोखिम स्तर और निवेश उद्देश्य को जरूर समझना चाहिए।

न खास फायदा, न नुकसान

लो NAV वाले म्यूचुअल फंड में निवेश करना अपने आप में न तो ज्यादा फायदेमंद होता है और न ही नुकसानदायक। असली फायदा सही फंड चुनने, लंबे समय तक निवेश बनाए रखने और अपने वित्तीय लक्ष्य के अनुसार योजना बनाने में है। समझदारी भरा निवेश वही है जिसमें NAV से ज्यादा फंड की गुणवत्ता और संभावनाओं पर ध्यान दिया जाए।

2026 में सिगरेट व कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर महंगा, बचत उत्सव के बाद क्या-क्या बदल रहा?

जीएसटी बचत उत्सव' के बाद 2026 में कुछ मोर्चों पर महंगाई की वापसी दिखी है। सिगरेट, कमर्शियल एलपीजी और हाउसिंग सोसाइटी मेंटेनेंस हुए महंगे, लेकिन आटा-दाल जैसी आवश्यक वस्तुएं अब भी सस्ती रहने का अनुमान है। जानिए कीमतों के मोर्चे पर नए साल में क्या-क्या बदलने वाला है।

सितंबर 2025 में लागू हुए 'जीएसटी 2.0' (GST 2.0) या 'जीएसटी बचत उत्सव' के बाद आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली थी, लेकिन साल 2026 की शुरुआत के साथ ही महंगाई का दबाव फिर से कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में दिखने लगा है। जहां एक ओर आवश्यक वस्तुएं सस्ती बनी हुई हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार की नई राजकोषीय रणनीतियों और इनपुट लागत में वृद्धि के कारण 'सिन गुड्स', कमर्शियल एलपीजी और हाउसिंग सोसाइटी के मेंटेनेंस जैसे खर्चों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर कर का नया ढांचा

1 फरवरी 2026 से जीएसटी मुआवजा उपकर की आधिकारिक समाप्ति के साथ ही सरकार ने राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए नए कानून पेश किए हैं। इसका सबसे बड़ा असर तंबाकू और सिगरेट की कीमतों पर पड़ा है। 'केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम 2025' के तहत अब सिगरेट पर 40% जीएसटी के साथ एक 'विशेष उत्पाद शुल्क' लगाया गया है, जो सिगरेट की लंबाई पर आधारित है।

जानकारों के मुताबिक, नई व्यवस्था में कर का भार वास्तविक रूप से बढ़ा है। एफएमसीजी कंपनियां इस अतिरिक्त बोझ को सीधे उपभोक्ताओं पर डाल सकती हैं, जिससे रिटेल कीमतों में 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। इसके अलावा, पान मसाला निर्माताओं पर अब वास्तविक बिक्री के बजाय उनकी मशीनों की उत्पादन क्षमता के आधार पर उपकर लगाया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र में भी कीमतें बढ़ सकती हैं।

शहरी मध्यम वर्ग और सेवा क्षेत्र पर 'परोक्ष' मार

महंगाई की यह नई लहर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में आई है।1 जनवरी 2026 से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 111 रुपये की भारी वृद्धि की गई है। हालांकि घरेलू गैस की कीमतें स्थिर हैं, लेकिन कमर्शियल गैस महंगी होने से रेस्तरां, होटल और कैंटीन की लागत बढ़ेगी, जिससे बाहर खाना खाना महंगा हो सकता है।

वहीं, शहरी मध्यम वर्ग के लिए एक 'छिपी हुई लागत' सामने आई है। जीएसटी अधिकारियों ने उन हाउसिंग सोसायटियों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है जहां मासिक रखरखाव शुल्क 7,500 रुपये प्रति सदस्य से अधिक है। यदि शुल्क इस सीमा से एक रुपये भी अधिक है, तो पूरी राशि पर 18% जीएसटी लागू होगा। यह नोएडा, गुरुग्राम और मुंबई जैसे शहरों में रहने वाले परिवारों के लिए एक बड़ा वित्तीय झटका है।

किन क्षेत्रों में राहत की उम्मीद?

ऑटोमोबाइल सेक्टर जीएसटी 2.0 का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है। पुरानी व्यवस्था (28% जीएसटी + उपकर) की तुलना में नई दरों (18% या 40% फ्लैट) ने कारों की कीमतों में भारी कमी की है। उदाहरण के लिए, छोटी कारों पर कर का बोझ 29% से घटकर 18% रह गया है।

हालांकि, जनवरी 2026 से मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और हुंडई जैसी कंपनियों ने इनपुट लागत (स्टील, प्लास्टिक) और विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव के कारण कीमतों में 0.6 से 3% की वृद्धि की है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस मामूली वृद्धि के बावजूद, जीएसटी कटौती के कारण कारें अभी भी 2024 की तुलना में काफी सस्ती हैं।

महंगाई की चिंताओं के बीच राहत की बात यह है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें नियंत्रण में हैं। रिपोर्टों के अनुसार, आटा, चावल, दवाइयां और स्वास्थ्य बीमा जैसी चीजें सस्ती बनी हुई हैं क्योंकि इन्हें या तो 0% या 5% के न्यूनतम स्लैब में रखा गया है। अच्छे मानसून और पर्याप्त बफर स्टॉक के कारण 2026 में खाद्य मुद्रास्फीति के भी सीमित दायरे में रहने की उम्मीद है।

कुल मिलाकर 2026 का आर्थिक परिदृश्य मिश्रित है। सरकार ने आवश्यक वस्तुओं को सस्ता रखकर अपना वादा निभाया है, लेकिन 'सिन गुड्स' और विलासिता की वस्तुओं पर कर बढ़ाकर राजस्व संतुलन बनाने की कोशिश की है। उपभोक्ताओं के लिए चुनौती अब उन वस्तुओं और सेवाओं में है जो बाजार की इनपुट लागत और नए उपकर नियमों से प्रभावित हैं।

ग्रेच्युटी पर सरकार का बड़ा फैसला, इनको मिलेगा डबल फायदा

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी केवल एक शब्द नहीं, बल्कि रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षा की गारंटी है। लेकिन क्या हो अगर आपने जीवन में दो अलग-अलग सरकारी संस्थाओं में काम किया हो? क्या आपको दो बार ग्रेच्युटी मिलेगी या सरकार दूसरे कार्यकाल के पैसे काट लेगी? इसी उलझन को सुलझाते हुए केंद्र सरकार के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने एक बेहद अहम स्पष्टीकरण जारी किया है। नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के लिए जारी किए गए इस नए आदेश में साफ किया गया है कि कब आपकी ग्रेच्युटी पर 'लिमिट' लगेगी और कब आपको पूरा फायदा मिलेगा।

सरकार ने मेमोरेंडम में 'CCS Amendment Rules, 2025' के नियम 4A को आधार बनाया है। आसान भाषा में समझें तो यह नियम 'डबल बेनिफिट' को रोकता है। विभाग ने साफ किया है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है और उसे उसकी ग्रेच्युटी मिल चुकी है, तो दोबारा सरकारी नौकरी (Re-employment) ज्वाइन करने पर उसे उस दूसरे कार्यकाल के लिए अलग से ग्रेच्युटी नहीं दी जाएगी। यानी, एक बार सरकारी खजाने से रिटायरमेंट ग्रेच्युटी लेने के बाद, उसी सिस्टम में री-एम्प्लॉयमेंट पर दोबारा ग्रेच्युटी का दावा नहीं किया जा सकता। इस आदेश में उन कर्मचारियों के लिए नियम थोड़े अलग हैं जो किसी पीएसयू (PSU) या स्वायत्त निकाय से विधिवत अनुमति लेकर केंद्र सरकार की सेवा में आए हैं। ऐसे कर्मचारियों के लिए खबर थोड़ी राहत भरी है, लेकिन एक शर्त के साथ। अगर आप PSU से आए हैं, तो आपको वहां की ग्रेच्युटी रखने का हक है और केंद्र सरकार की सेवा के लिए भी ग्रेच्युटी मिलेगी। लेकिन, यहां सरकार ने एक 'सीलिंग' लगा दी है। नियम के मुताबिक, दोनों जगहों से मिली कुल ग्रेच्युटी की रकम उस राशि से ज्यादा नहीं हो सकती, जो कर्मचारी को तब मिलती अगर उसने अपनी पूरी सेवा (PSU + केंद्र सरकार) लगातार केंद्र सरकार में ही की होती। यही फार्मूला उन लोगों पर भी लागू होगा जो राज्य सरकार की नौकरी छोड़कर केंद्र में आए हैं। कुल मिलाकर, दो जेबों से पैसा तो आएगा, लेकिन उसकी कुल सीमा आपकी फाइनल सैलरी और कुल सेवा अवधि के आधार पर तय होगी। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी राहत हमारे पूर्व सैनिकों के लिए है। सरकार के पास कई सवाल आ रहे थे कि मिलिट्री सर्विस के बाद सिविल सर्विस ज्वाइन करने वालों का क्या होगा?

ईरान सीमा पर डेल्टा फोर्स की तैनाती, तेहरान से रूस में सोना ले जाने का दावा...खामेनेई का गेमओवर?

तेहरान। ईरान में जारी बवाल के बीच अली खामेनेई के गेमऑवर की चर्चा जोरों पर है। एक तरफ अमेरिका ने ईरान बॉर्डर पर अपने डेल्टा फोर्स को तैनात कर दिया है। यह वही डेल्टा फोर्स है, जिसके सैनिकों ने हाल ही में वेनेजुएला में निकोलस मादुरो के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया था। अमेरिका ने डेल्टा फोर्स की तैनाती पर आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा है।

वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश अधिकारी ने दावा किया है कि तेहरान में एक रूसी प्लेन उतारा गया है, जो सोना लेकर मॉस्को वापस जाएगा। द टाइम्स के मुताबिक अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो खामेनेई मॉस्को जा सकते हैं। ईरान ने इस रिपोर्ट का कोई खंडन नहीं किया है।

ईरान में नहीं रूक रहा है विरोध-प्रदर्शन

ईरान में 12 दिन से विरोध प्रदर्शन जारी है। 26 प्रांतों में लोग खामेनेई सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। ईरान सरकार ने लोगों को मनाने के लिए हर नागरिक को 7 डॉलर प्रतिमाह मुफ्त में देने का भी ऐलान किया था, लेकिन लोग तब भी वापस नहीं जा रहे हैं। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहीं पीपुल्स मुजाहिद संगठन प्रमुख मरियम रजवी के मुताबिक लोग खामेनेई को सत्ता से हटाना चाहते हैं। लोगों की कोशिश नई सरकार चुनने की है। खामेनेई को हटाकर 15 दिनों के भीतर अगर चुनाव कराया जाता है तो हम सड़कों पर से हट जाएंगे। रिजवी के मुताबिक 1979 के बाद यह बड़ा विरोध प्रदर्शन है। इसमें छात्र, महिला, व्यापारी और किसान वर्ग शामिल हैं। इस प्रदर्शन को ग्रामीण स्तरों पर भी सपोर्ट मिल रहा है। खामेनेई को आखिर में जाना ही होगा। वहीं ईरान सरकार का कहना है कि मोसाद और सीआईए के एजेंट प्रदर्शन को हवा दे रहे हैं। यह हमारा आंतरिक मामला है और हम इससे निपट लेंगे।

ग्राहम लिंडसे ने तख्तापलट की बात स्वीकारी

रिपब्लिकन सीनेटर और डोनाल्ड ट्रंप के करीबी ग्राहम लिंडसे ने ईरान में अमेरिकी भूमिका को लेकर बड़ा खुलासा किया है। ग्राहम ने कहा कि हम वहां तख्तापलट की कोशिश में जुटे हैं। अमेरिका के लोग पूरी तरह से ईरानियों के साथ है, इसलिए हम उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। 1953 में भी ईरान में अमेरिका तख्तापलट कर चुका है। उस वक्त सीआईए ने महंगाई को ही मुद्दा बनाकर ईरान सरकार का तख्तापलट किया था।

खामेनेई को हटाने के लिए अब मुनीर करेंगे US की मदद? बदले में ट्रंप से मिलेंगे ये खास तोहफे

तेहरान। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका के धमकी देने के बाद अब ईरान की तरफ से भी धमकी दी गई है। इस बीच अब अमेरिका ने किसी भी तरह के संभावित एक्शन के लिए बाकी देशों को भी अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में अब अमेरिका अपने ईरान के खिलाफ एक्शन के लिए पाकिस्तान का भी इस्तेमाल कर सकता है। इसको लेकर एक सीक्रेट डेलीगेशन पाकिस्तान भी पहुंचा था।

दो दिन पहले एक जॉइंट US-इजराइली सीक्रेट डेलीगेशन पाकिस्तानी सेना और इंटेलिजेंस एजेंसियों से सलाह और मदद लेने के लिए इस्लामाबाद पहुंचा था। ताकि ईरानी शासन को हटाने की कोशिशों में तालमेल बिठाया जा सके।

जानकारी के मुताबिक, US-इजराइली सीक्रेट डेलीगेशन ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ कुछ सीक्रेट बाइलेटरल एग्रीमेंट भी किए, जिनमें सबसे अहम यह था कि अगर ईरानी शासन के खिलाफ संभावित युद्ध तेज होता है, तो पाकिस्तान को अमेरिका और इजराइल को मिलिट्री और लॉजिस्टिक सपोर्ट देना चाहिए, साथ ही ईरान में मौजूदा शासन के खिलाफ सिस्टमैटिक प्रोपेगैंडा में पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए और ईरानी लोगों के मन में नए शासन के पक्ष में पब्लिक ओपिनियन बनाने में भी मदद करनी चाहिए।

अमेरिका और इजराइली डेलीगेशन इस पाकिस्तानी मदद के बदले में जनरल आसिम मुनीर पर उनकी तानाशाही नीतियों के कारण दबाव नहीं डालेंगे और पाकिस्तान को सीक्रेट फाइनेंशियल मदद भी देंगे। सूत्रों का यह भी दावा है कि अगर जरूरत पड़ी, तो पाकिस्तान अमेरिका और इजराइल को अपने समुद्री क्षेत्र और कुछ खास एयर बेस का इस्तेमाल करने की इजाजत दे सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच पिछले दिनों से टकराव बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच जहां लगातार ट्रंप ईरान को धमकी देते रहे हैं। वहीं, अब ईरान के सेना प्रमुख मेजर जनरल अमीर हातामी ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान को निशाना बनाने वाली बयानबाजी पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक (पूर्व-निवारक हमले) की धमकी दी।

ईरान में इस समय आर्थिक संकट को लेकर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। देश में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इन प्रदर्शनों में अब तक कई लोगों की मौत हो गई है। वहीं, कई को गिरफ्तार भी किया गया है। इस बीच अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि अगर तेहरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हिंसक हत्या करना बंद नहीं करता है, तो अमेरिका उनकी मदद के लिए आएगा।

झूठ बोलकर पाकिस्तान ने कितने देशों को बेचा जे.एफ-17 लड़ाकू विमान, अब बांग्लादेश को फंसाया

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान ने दावा किया है कि बांग्लादेश ने उससे लड़ाकू विमान JF-17 खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। ऑपरेशन सिंदूर में मात खाने वाला पाकिस्तान झूठ बोलकर ये हल्का फाइटर जेट बेच रहा है। उसकी सेना ने बांग्लादेश से दावा किया कि सिंगल-इंजन वाला यह हल्का फाइटर जेट मई में भारत के साथ हुए टकराव के दौरान अपनी काबिलियत साबित कर चुका है।

पाकिस्तान दुनिया को एक झूठ और बता रहा है। उसके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ डिफेंस ऑर्डर इतने बढ़ गए हैं कि पाकिस्तान जल्द ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) से लोन लेना बंद कर सकता है।

ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराया गया था जे.एफ-17

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के सामने JF-17 की सीमाएं साफ तौर पर सामने आ गई थीं। भारत ने पाकिस्तान के कई F-16 और JF-17 एयरक्राफ्ट और मार गिराए थे। उस ऑपरेशन में भारत की एयर डॉमिनेंस, बेहतर रडार नेटवर्क और आधुनिक फाइटर प्लेटफॉर्म के आगे पाकिस्तानी वायुसेना धूल चाटती नजर आई थी।

जे.एफ-17 एयरक्राफ्ट की खासियत...

JF-17C ब्लॉक III, JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट का एक एडवांस्ड वर्जन है, जिसे चीन की चेंगदू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन और पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने मिलकर बनाया है। JF-17 एक 4.5-जेनरेशन, सिंगल-इंजन, मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो मॉडर्न एवियोनिक्स, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार और एडवांस्ड हथियारों से लैस है। इसे हर मौसम में ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह हवा से हवा और हवा से ज़मीन दोनों तरह की लड़ाई में सक्षम है। चीनी कंपोनेंट्स के अलावा, यह एयरक्राफ्ट तुर्की के वेपन सिस्टम से भी लैस है।

अजरबैजान को बेच चुका है विमान

पाकिस्तान इससे पहले अजरबैजान को JF-17C ब्लॉक III फाइटर एयरक्राफ्ट बेच चुका है। 25 सितंबर, 2024 को अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने बाकू के हैदर अलीयेव इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक डिफेंस एग्जीबिशन के दौरान पाकिस्तान से JF-17C ब्लॉक III फाइटर एयरक्राफ्ट का पहला बैच लिया था। अगले दिन पाकिस्तानी सेना ने अपने डिफेंस कोऑपरेशन के तहत अजरबैजान को JF-17C की बिक्री की पुष्टि की। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान ने अजरबैजान को JF-17 एयरक्राफ्ट बेचने के लिए 1.6 बिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है।

इन देशों को भी बेच चुका है पाकिस्तान

पाकिस्तान म्यांमार, नाइजीरिया, लीबिया को भी ये लड़ाकू विमान बेच चुका है। 2015 में पाकिस्तान ने म्यांमार को JF-17 फाइटर जेट बेचने का सौदा किया था। इसके तहत 2018 से 2021 के बीच म्यांमार को 11 JF-17 विमान सप्लाई किए गए। नाइजीरिया 2016 में तीन यूनिट ऑर्डर करके JF-17 का दूसरा ग्राहक बना था। 2021 में एयरफोर्स में शामिल होने के बाद से इस एयरक्राफ़्ट को आतंकवाद विरोधी और विद्रोह विरोधी ऑपरेशन्स में तैनात किया गया है। पिछले महीने इस्लामाबाद ने लीबिया की पूर्वी स्थित लीबियन नेशनल आर्मी के साथ 4 अरब डॉलर से ज़्यादा का हथियारों का सौदा किया, जो देश की अब तक की सबसे बड़ी हथियारों की बिक्री में से एक है। इसमें JF-17 फाइटर जेट और ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट शामिल हैं।

सऊदी अरब के साथ चल रही बातचीत

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, पाकिस्तान और सऊदी अरब करीब 2 अरब डॉलर के सऊदी कर्ज को JF-17 फाइटर जेट डील में बदलने के लिए बातचीत कर रहे हैं। यह पिछले साल दोनों देशों के बीच आपसी रक्षा समझौते पर साइन होने के कुछ महीनों बाद सैन्य सहयोग को और गहरा करेगा। सूत्र ने बताया कि बातचीत सिर्फ JF-17 थंडर फाइटर जेट्स देने तक ही सीमित थी, जो पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाया है , जबकि दूसरे ने कहा कि ये जेट्स बातचीत में शामिल दूसरे ऑप्शन में से मुख्य ऑप्शन थे। रिटायर्ड एयर मार्शल और एनालिस्ट आमिर मसूद ने रॉयटर्स को बताया कि पाकिस्तान छह देशों के साथ JF-17 और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और जेट के लिए वेपन सिस्टम समेत इक्विपमेंट देने के लिए बातचीत कर रहा है या डील फाइनल कर चुका है। उन्होंने कहा कि इन देशों में सऊदी अरब भी शामिल है, लेकिन वह बातचीत के बारे में कोई डिटेल कन्फर्म नहीं कर सके।

फेल रहा है JF-17

पाकिस्तान भले ही झूठ बेचकर JF-17 विमान बेच रहा हो, लेकिन जमीन पर ये पूरी तरह से फेल रहा है। कई रिपोर्ट्स में JF-17 के इंजन, रडार सिस्टम और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी में दिक्कतों का दावा किया गया है। हथियारों की टारगेट पर लगने की सटीकता भी बहस का मुद्दा है। 27 फरवरी 2019 को भारत से तनाव के वक्त भी पाकिस्तान एयरफ़ोर्स का JF-17 विमान नाकाम रहा था। पिछले साल जून के महीने में म्यांमार एयरफोर्स का एक JF-17 फाइटर जेट आसमान से आग का गोला बनकर जमीन पर गिर पड़ा था। म्यांमार के विद्रोही गुट पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने दावा किया था कि उन्होंने ही इस फाइटर जेट को मार गिराया है।

प्रतीक के घर ईडी की रेड से बिफरीं सीएम ममता, पूछा– क्या ये तलाशी गृह मंत्री का काम?

कोलकाता, एजेंसी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के आईटी प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रतीक जैन के घर पर ईडी की छापेमारी को लेकर नाराजगी जताई। इस दौरान सीएम ममता प्रतीक जैन के आवास पर पहुंचीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, 'यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि ईडी ने टीएमसी के आईटी प्रमुख के घर पर छापा मारा।'

ममता बनर्जी ने टीएमसी के आईटी प्रमुख के घर पर ईडी की छापेमारी पर सवाल खड़े करते हुए कहा, 'क्या राजनीतिक दलों के आईटी प्रमुखों के घरों पर छापा मारना केंद्रीय गृह मंत्री का काम है?' जानकारी के मुताबिक वित्तीय अनियमितताओं के मामले में प्रतीक जैन के घर पर ईडी ने छापेमारी की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि ईडी के अधिकारी आईपीएसी प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर तलाशी अभियान के दौरान टीएमसी की हार्ड डिस्क, आंतरिक दस्तावेज और संवेदनशील संगठनात्मक डेटा जब्त करने का कोशिश कर रहे थे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि टीएमसी के आईटी प्रमुख के घर पर ईडी की छापेमारी राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित और असंवैधानिक है, यह गृह मंत्री का सबसे घिनौना काम है।

ममता बनर्जी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, 'उन्होंने हमारे आईटी प्रमुख के आवास पर छापा मारा था। वे मेरी पार्टी के दस्तावेज और हार्ड डिस्क जब्त कर रहे थे, जिनमें विधानसभा चुनावों के लिए हमारे उम्मीदवारों का विवरण था। मैंने उन्हें वापस ले लिया है।' उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ईडी ये सारे दस्तावेज जब्त कर भाजपा को देने जा रही थी।

ईडी ने गुरुवार को देश के 6 राज्यों के 15 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने इंडियन पॉलिटकल एक्शन कमेटी (आईपीएसी) के कोलकाता के ऑफिस पर छापेमारी की। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक ईडी ने सरकारी नौकरी दिलाने के फर्जी दावे के घोटाले की जांच में छापेमारी की है। ईडी का कहना है कि एक समूह लोगों को फर्जी नौकरियां दिलाने के नाम पर ठग रहा है।

राज ठाकरे ने भाजपा को बताया खतरा, नगर निकाय चुनाव में मराठी अस्मिता का मुद्दा कितना बड़ा?

मुंबई, एजेंसी। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि जो ताकतें मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करना चाहती हैं, वही आज केंद्र और राज्य की सत्ता में हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर नगर निकायों पर भी ऐसी शक्तियों का नियंत्रण हो गया, तो मराठी मानूस पूरी तरह कमजोर हो जाएगा।

राज ठाकरे और शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे का संयुक्त साक्षात्कार का पहला भाग गुरुवार को सामना में प्रकाशित हुआ। इसमें राज ठाकरे ने कहा कि वह और उनके चचेरे भाई किसी राजनीतिक अस्तित्व के लिए नहीं, बल्कि महाराष्ट्र में मराठी मानूस के अस्तित्व और अधिकारों की रक्षा के लिए एक साथ आए हैं।

ठाकरे परिवार के चचेरे भाइयों का साक्षात्कार शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सदस्य और सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत और जाने-माने निर्देशक महेश मांजरेकर ने लिया। पिछले महीने, चचेरे भाइयों

ने 15 जनवरी को होने वाले बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों के लिए अपनी पार्टियों के गठबंधन की घोषणा की थी। इंटरव्यू में राज ठाकरे ने कहा कि राज्य के बाहर से आने वाले लोग न केवल आजीविका के लिए आ रहे हैं, बल्कि वे अपने स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र बना रहे हैं। उन्होंने दावा किया, 'यह एक पुराना घाव है... मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने के सपने को साकार करने के प्रयास जारी हैं।' उन्होंने कहा कि आज का माहौल कुछ वैसा ही है जैसा संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के दौरान था जब गुजरात मुंबई को अपना हिस्सा बनाना चाहता था। उन्होंने दावा किया, 'अगर भाजपा नगर निगमों पर नियंत्रण कर लेती है तो मराठी मानुष कुछ भी नहीं कर पाएंगे।'

नगर निकायों को नियंत्रित करना जरूरी

एमएनएस प्रमुख ने कहा कि अगर इस पर सीमाएं तय करनी हैं तो नगर निकायों को नियंत्रित करना जरूरी है, खासकर मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक, मीरा-भयंदर, कल्याण-डोम्बिवली और छत्रपति संभाजीनगर में। राज्य सरकार को निशाना बनाते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाजपा विकास का प्रचार करती है, लेकिन इससे प्रगति के बजाय विनाश होता है। उन्होंने दावा किया कि यह 'बिना योजना के विकास' है।

भाजपा सरकार को खुद नहीं पता कि वे क्या चाहती है

पूर्व राज्य मुख्यमंत्री ने आगे कहा, 'सरकार को खुद नहीं पता कि वह क्या चाहती है।' उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से, सत्ता में बैठे लोग मराठी या महाराष्ट्र से हैं, लेकिन उनका मुंबई की जनता से कोई लेना-देना नहीं है। वे केवल ठेकेदारों के लिए काम करते हैं।

मादप पदार्थों के खतरे को लेकर राज्य सरकार पर साधा निशाना

राज ठाकरे ने बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजनीति में धन के इस्तेमाल और आसानी से उपलब्ध मादक पदार्थों के बीच संबंध स्थापित करना आवश्यक है। उन्होंने दावा किया कि नशीली दवाओं के खिलाफ छापे बंद हो गए हैं और राज्य में नशीली दवाओं की तस्करी पर कोई नियंत्रण नहीं है।

राहु केतु का ट्रेलर रिलीज, बड़े पर्दे पर अब मचेगा कॉस्मिक कॉमेडी का बवाल

ज़ी स्टूडियोज़ और ब्लाइव प्रोडक्शन्स के बैनर तले बनी फिल्म राहु केतु का बहुप्रतीक्षित ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और आते ही इसने साफ कर दिया है कि दर्शकों को मिलने वाला है एक ऐसा पागलपन भरा सफर, जहां पौराणिक कथाएं टकराएंगी आज के हंगामे से और हंसी के पीछे छुपा होगा एक बड़ा कॉस्मिक मैसेज। चुटीले ह्यूमर, शार्प राइटिंग और दमदार परफॉर्मेंस से भरा यह ट्रेलर एक ऐसी फिल्म का वादा करता है, जो जितनी एंटरटेनिंग है, उतनी ही सोचने पर मजबूर करने वाली भी। ट्रेलर की शुरुआत होती है पियूष मिश्रा की प्रभावशाली आवाज़ से, जो अपनी खास कहानी कहने की शैली में राहु और केतु के पौराणिक महत्व से दर्शकों को रूबरू कराते हैं। उनकी आवाज़ लोककथाओं की जड़ों में कहानी को मजबूती से बांधती है और एक ऐसी दुनिया की नींव रखती है, जहां प्राचीन मान्यताएं टकराती हैं आज के मॉडर्न कन्फ्यूज़न से। फिल्म की कमान संभालते हैं पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा, जिनकी कॉमिक टाइमिंग और आपसी केमिस्ट्री ट्रेलर में ही दिल जीत लेती है। पुलकित अपने किरदार में चार्म, चालाकी और अनिश्चितता लेकर आते हैं, जो शॉर्टकट और महत्वाकांक्षा से चलने वाला है। वहीं वरुण शर्मा एक बार फिर साबित करते हैं कि सिचुएशनल कॉमेडी उनका मजबूत हथियार है, जहां उनका फिज़िकल ह्यूमर और ऑब्ज़र्वेशनल कॉमिक सेंस खूब रंग जमाता है। फिल्म की थीम पर बात करते हुए पुलकित सम्राट कहते हैं, फैंटेसी की दुनिया हमेशा से मुझे आकर्षित करती रही है। राहु केतु में जो बात मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगी, वो था इस रंगीन और अराजक यूनिवर्स का हिस्सा बनना, जो पूरी तरह कॉमेडी से जुड़ा है।

पौराणिक विचारों को मज़ेदार और आसान अंदाज़ में, खासकर बच्चों के लिए, ज़दिा होते देखना और उस सफर का हिस्सा बनना मेरे लिए बेहद खुशी की बात रही। वहीं वरुण शर्मा जोड़ते हैं, राहु केतु का ह्यूमर पूरी तरह सिचुएशंस और इंसानी कमज़ोरियों से निकला है। हम सिर्फ लोगों को हंसा नहीं रहे, बल्कि एक आईना दिखा रहे हैं, बस थोड़ा सा पागलपन, ढेर सारी मस्ती और अराजकता के साथ। शालिनी पांडे ट्रेलर में एक मजबूत और आत्मविश्वासी अवतार में नज़र आती हैं। उनका किरदार कहानी को भावनात्मक गहराई देता है और फिल्म की नैतिक रीढ़ को मज़बूती से थामे रखता है, जिससे स्क्रीन पर चल रहे पूरे हंगामे को एक ठोस दिशा मिलती है।

अपने किरदार के बारे में बात करते हुए शालिनी पांडे कहती हैं, राहु केतु मेरे करियर के सबसे मज़ेदार सफरों में से एक रहा है। विपुल विग का विज़न बहुत स्पष्ट है, लेकिन वह अपने कलाकारों को अपनी सहज प्रवृत्ति लाने की पूरी आज़ादी देते हैं, जिससे काम करने का अनुभव बेहद खास बन जाता है। अपने को-एक्टर्स के साथ काम करना शानदार रहा और ज़ी स्टूडियोज़ व ब्लाइव प्रोडक्शन्स ने जिस भरोसे और जुनून के साथ फिल्म को सपोर्ट किया है, वह स्क्रीन पर साफ झलकता है। मैं दर्शकों के रिएक्शन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूं। सपोर्टिंग कास्ट भी ट्रेलर की जान है।

चंकी पांडे अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग के साथ एक और यादगार परफॉर्मेंस देते हैं, वहीं अमित सियल अपनी संयमित और गहरी अदायगी से फिल्म के हाई एनर्जी पागलपन को ज़मीन पर टिकाए रखते हैं। राहु केतु को सबसे अलग बनाता है खुद राहु और केतु का पौराणिक रूप में आगमन, जो कहानी को एक बड़े दार्शनिक स्तर पर ले जाता है। उनकी मौजूदगी फिल्म के मूल संदेश को मजबूती देती है—जैसा करोगे, वैसा भरोगे—और यह सब हंसी, अफरातफरी और कॉस्मिक असर के साथ बेहद सहज तरीके से पिरोया गया है। पौराणिकता, कॉमेडी और सामाजिक सोच का यह अनोखा मेल राहु केतु को एक ऐसी सिनेमाई पेशकश बनाता है, जो दिमाग को भी छूती है और दिल को भी हंसाती है। यह फिल्म 16 जनवरी 2026 को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है।

रीना रॉय : पर्दे की पहली नागिन ने जब चुराया लोगों का दिल, हर रोल में दिखीं बेहद खास

बॉलीवुड की दुनिया में कई कलाकार हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जो हर तरह के किरदार को इतनी मजबूती से निभाते हैं कि दर्शक उन्हें हमेशा याद रखें। रीना रॉय भी उन्हीं में से एक हैं। चाहे कोई रोल नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उनकी परफॉर्मेंस में हमेशा आत्मविश्वास देखने को मिलता है। 1970 और 1980 के दशक में उन्होंने जिस तरह से फिल्मों में खुद को साबित किया, वह आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा है। उनकी खूबसूरती और अभिनय क्षमता ने उन्हें सिर्फ हिट फिल्मों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने हर किरदार से अपनी छाप छोड़ी। रीना रॉय का जन्म 7 जनवरी 1957 को मुंबई में हुआ था। उनका असली नाम सायरा अली था। उनका परिवार फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा था। उनके पिता, सादिक अली, अभिनेता थे, और उनकी मां, शारदा रॉय, भी फिल्मों में काम करती थीं। माता-पिता के तलाक के बाद, उनका नाम बदलकर पहले रूपा रॉय और फिर फिल्म निर्माता की सलाह पर रीना रॉय रखा गया। उनकी रुचि बचपन से ही अभिनय में थी।

रीना ने 1972 में फिल्म जरूरत से अपने करियर की शुरुआत की। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं हुई, लेकिन रीना की परफॉर्मेंस ने दर्शकों और फिल्म निर्माताओं का ध्यान खींचा। इसके बाद उन्होंने 1973 में जैसे को तैसा और 1975 में जख्मी जैसी फिल्मों में काम किया। उन्होंने फिल्मों में नेगेटिव किरदारों के जरिए अभिनय की ताकत दिखाई।

1976 में रीना के करियर का सुनहरा मोड़ आया। उन्होंने कालीचरण और नागिन जैसी फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाईं। कालीचरण में उनकी केमिस्ट्री शत्रुघ्न सिन्हा के साथ पसंद की गई, जबकि नागिन में उन्होंने एक इंसान और नागिन के रूप में जटिल भूमिका निभाई। इस फिल्म ने उन्हें बॉक्स ऑफिस स्टार बना दिया। इस समय उनकी खूबसूरती के साथ-साथ किरदार निभाने की मजबूती ने दर्शकों को प्रभावित किया।

1977 में रीना ने अपनापन में काम किया और फिल्मफेयर अवॉर्ड के लिए नामांकित हुई। इसके बाद उन्होंने 1980 में आशा, 1981 में नसीब, और 1982 में सनम तेरी कसम जैसी हिट फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में उन्होंने अलग-अलग किरदार निभाए, कभी प्यार में हारी प्रेमिका की, तो कभी संस्कारी बहू की, तो कभी साहसी महिला की, उनके किरदारों में हमेशा गहराई और मजबूती देखने को मिलती थी।

रीना रॉय ने अपने करियर में कई बड़े सितारों के साथ काम किया। उन्होंने जितेंद्र के साथ कई हिट फिल्में दीं, जैसे बदलते रिश्ते, अर्पण, और आशा। उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के साथ भी कई हिट फिल्में कीं। उनके किरदार चाहे नेगेटिव हों या पॉजिटिव, हमेशा दर्शकों के दिलों पर असर छोड़ते थे। उनके अभिनय की यही खासियत उन्हें अलग बनाती है।

1983 में रीना ने अपने करियर में ब्रेक लिया और पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी की। बाद में उनका तलाक हो गया और वे भारत लौट आईं। 1993 में उन्होंने आदमी खिलौना है में वापसी की, लेकिन उनकी पुरानी लोकप्रियता दोबारा नहीं बन सकी। इसके बाद उन्होंने कुछ और फिल्मों में सहायक भूमिका निभाई, जैसे अजय (1996), गैर (1999) और रिफ्यूजी (2000)।

रीना ने फिल्मों के अलावा टीवी में भी काम किया। उन्होंने ईना मीना डीका, दाल में काला है, सहारा, और गैर जैसे टीवी शो में काम किया है।

लंबे समय बाद सेट पर लौटीं कंगना रनौत, शुरू की भारत भाग्य विधाता की शूटिंग

बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी से सांसद कंगना रनौत काफी समय से फिल्मों से दूर और राजनीति में ज्यादा सक्रिय हैं। अभिनेत्री ने शीतकालीन सत्र में कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा था, लेकिन अब काफी समय बाद कंगना वापस फिल्मी सेट पर लौटी हैं। उन्होंने शूटिंग करते हुए वीडियो पोस्ट किया है। सेट पर वापसी करने का अनुभव अभिनेत्री के लिए खुश कर देने वाला है। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह मनोज तापड़िया के साथ दिख रही हैं। अभिनेत्री सेट पर बाकी लोगों के साथ मिलजुल रही हैं और मनोज तापड़िया उन्हें फिल्म के सीन भी समझा रहे हैं। उन्होंने वीडियो को शेयर कर लिखा, फिल्म के सेट पर वापसी कर अच्छा लग रहा है। कंगना फिल्म इमरजेंसी के बाद लंबे समय के बाद दूसरी फिल्म की शूटिंग कर रही हैं, जिसका नाम है भारत भाग्य विधाता।

इमरजेंसी के रिलीज के साथ कंगना ने भारत भाग्य विधाता की अनाउंसमेंट कर दी

थी, लेकिन अब तकरीबन एक साल बाद फिल्म की शूटिंग शुरू की गई है। भारत भाग्य विधाता को यूनोइया फिल्म्स की बबीता आशिवाल और फ्लोटिंग रॉक्स एंटरटेनमेंट के आदि शर्मा मिलकर प्रोड्यूस करने वाले हैं, जबकि डायरेक्ट मनोज तापड़िया करेंगे, जिन्होंने मद्रास कैफे, चीनी कम, एनएच10, और माई जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया है।

भारत भाग्य विधाता एक देशभक्ति फिल्म है, जिसमें उन महान वीरों की कहानियों को दिखाया जाएगा, जिनके बारे में कम ही लोगों को पता है। फिल्म की कहानी वीरता और साहस की भावना से भरी होने वाली है, लेकिन फिल्म कब रिलीज होगी, इस बारे में जानकारी सामने नहीं आई है।

बता दें कि अभिनेत्री की आखिरी रिलीज फिल्म इमरजेंसी सिनेमाघरों में फ्लॉप साबित हुई थी। फिल्म के रिलीज पर भी बैन लगा दिया गया था, लेकिन कुछ बदलावों के साथ फिल्म को रिलीज की अनुमति मिल गई। इमरजेंसी का निर्माण और निर्देशन दोनों ही कंगना ने किया था। इसके अलावा, फिल्म में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल भी प्ले किया था। इस फिल्म के लिए कंगना ने खूब मेहनत की थी, लेकिन फिर भी फिल्म पर्दे पर कमाल नहीं दिखा पाई थी। फिल्म का बजट लगभग 60 करोड़ रुपए था, लेकिन फिल्म ने भारत में लगभग 20 करोड़ का कलेक्शन ही किया था। फिल्म ने अपने बजट का आधे से कम की कमाई की थी।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित।
शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com